

वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020 - 2025

वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत का निर्माण करना



वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020 - 2025

सशक्त और आर्थिक रूप से जागरूक भारत बनाने के लिए
बहुहितधारक दृष्टिकोण

विषयवस्तु

चुनिंदा संक्षिप्ताक्षरों की सूची.....	i
कार्यपालक सार.....	1
अध्याय 1: परिचय.....	4
अध्याय 2: प्रथम एनएसएफई के तहत प्रगति का अवलोकन (2013-2018)	9
अध्याय 3: आवश्यकताओं का आंकलन और महत्वपूर्ण अंतर.....	12
अध्याय 4: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025).....	19
अध्याय 5 : नीति निर्माण	22
अध्याय 6: कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना.....	24
अध्याय 7: निगरानी और मूल्यांकन.....	35
संदर्भ	37
अनुबंध - हितधारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल.....	38

आकृति, चार्ट और बॉक्स आइटम की सूची

आकृति 1: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025).....	21
आकृति 2: संस्थागत व्यवस्था प्रवाह चार्ट और प्रत्येक हितधारक की जिम्मेदारियां	32
चार्ट 1: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का लिंग-वार प्रतिशत.....	13
चार्ट 2: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का क्षेत्र-वार प्रतिशत.....	13
चार्ट 3: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का उपजीविका-वार प्रतिशत	14
चार्ट 4: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का वार्षिक आय-वार प्रतिशत	14
चार्ट 5: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का ग्रामीण-शहरी प्रतिशत.....	15
चार्ट 6: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का शिक्षा-वार प्रतिशत	15
चार्ट 7: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का सामाजिक श्रेणी-वार प्रतिशत	16
चार्ट 8: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का आयु-वार प्रतिशत (2019).....	16
बॉक्स आइटम 1: कार्य करते हुये सीखना.....	11
बॉक्स आइटम 2: वित्तीय साक्षरता के घटकों की ओईसीडी-आईएनएफई परिभाषा	12
बॉक्स आइटम 3: वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और सिविल सोसायटी.....	34

चुनिंदा संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एएमएफआई	भारतीय पारस्परिक निधि संघ
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीसी	व्यवसाय प्रतिनिधि
बीसीएफआई	भारतीय व्यवसाय प्रतिनिधि परिसंघ
बी.एड.	शिक्षा-स्नातक
बीआईआरडी	बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
बीएसबीडीए	सामान्य बचत बैंक जमा खाता
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास
सीआईएससीई	काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन
सीएफएल	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीएससी	कॉमन सर्विस सेंटर
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
एफएसटीटी	वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण
एफईडीएआई	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
एफईपीए	वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम
एफईटीपी	वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम
एफआईडीसी	वित्त उद्योग विकास परिषद
एफएलसी	वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसडीसी-एससी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप-समिति
जीपीएफआई	वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईईपीएफए	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
आईआईसीए	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
आईएनएफई	वित्तीय शिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क
आईओएससीओ	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईपीपीबी	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
एलडब्लूई	वामपंथी उग्रवाद
एम.एड.	शिक्षा निष्णात
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमडब्लूएवंसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमएचएवंएफडब्लू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमआईएवंबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एमएसडीएवंई	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसजेएवंई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमयूपीएएवंएचए	शहरी गरीबी उपशमन और आवासन कार्य मंत्रालय
एनसीईईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएस	नई पेंशन योजना
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनईआर	उत्तर-पूर्व क्षेत्र
एनएफएलएटी	राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षण
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसएफई	वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति
एनयूएलएम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमएमवाई	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पीएमजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएम-केएमवाई	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
पीएम-एसवाईएम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान
आरयूडीएसईटीआई	ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य

सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
टीजीएफआईएफएल	वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूपीआई	यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस

कार्यपालक सार

देश में वित्तीय समावेशन को मजबूत करना भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के चार विनियामकों (भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) के लिए महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यसूचियों में से एक रहा है। वित्तीय साक्षरता ग्राहकों को सटीक विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाकर वित्तीय समावेशन संबंधी लक्ष्य को पूरा करने को समर्थित करता है जिससे ग्राहकों की वित्तीय खुशहाली मिलती है।

2. पहले वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई : 2013-2018) की अवधि के पूरा होने के उपरांत, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-अध्यक्ष: माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री) के तहत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल- अध्यक्ष: उप गवर्नर, आरबीआई) द्वारा अबतक की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यनीति के तहत की गई प्रगति की समीक्षा और पिछले 5 वर्षों¹ में हुए विभिन्न प्रगतियों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)², को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के परामर्श से वित्तीय क्षेत्र के चार विनियामकों और अन्य संबंधित हितधारकों ने संशोधित एनएसएफई (2020-2025) तैयार की है।

3. एनएसएफई दस्तावेज़ का उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार, जो कि उनके धन के बेहतर प्रबंधन और भविष्य की योजना के लिए आवश्यक है, विकसित करने हेतु सशक्त बनाने के माध्यम से भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विजन को समर्थित करना है। सभी भारतीयों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो, इस हेतु यह कार्यनीति एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश करती है।

4. आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के विजन को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कार्यनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है:

¹ मोबाइल फोन की बढ़ती पहुंच, खुदरा डिजिटल लेनदेन, देश में बढ़ती वयस्क आबादी, भुगतान और लघु वित्त बैंकों का आरंभ, फिन-टेक प्लेयर और लोगो के द्वारा वित्त का प्रबंधन करने की आवश्यकता पर जागरूकता।

² पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अगस्त 2014 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ सं. 6 (अध्याय -01) में फुट नोट सं.3 हेतु दिये गए स्पष्टीकरण को देखें।

- i. वित्तीय शिक्षण के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों को वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को आत्मसात करने एवं उसे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए प्रेरित करना
- ii. सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना
- iii. वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- iv. क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और आवश्यकतानुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना
- v. सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना
- vi. प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना
- vii. उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना
- viii. अधिकारों, कर्तव्यों और शिकायत निवारण के लिए माध्यमों के बारे में जानकारी
- ix. वित्तीय शिक्षण में प्रगति का आंकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार

5. निर्धारित कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इस दस्तावेज़ में प्रासंगिक **सामग्री** (स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम सहित) के विकास, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच **क्षमता** का विकास, उपयुक्त **संचार** कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए **सामुदायिक** नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाने, और अंत में विभिन्न हितधारकों के बीच **सहयोग** बढ़ाने के माध्यम से वित्तीय शिक्षण के प्रसार हेतु '5 सी' दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश की गई है।

6. कार्यनीति में प्रत्येक '5 सी' के तहत निर्धारित सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

सामग्री

- स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सह-शैक्षिक सहित), शिक्षकों, युवा व्यस्कों, महिलाओं, कार्यस्थल पर आए नए लोगो/ उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री।

क्षमता

- ऐसे विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं के क्षमता को विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु शामिल किए जा सकें।
- वित्तीय शिक्षण प्रदाताओं के लिए एक 'आचार संहिता' विकसित करना।

सामुदायिक

- धारणीय रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण का निर्माण।

संचार

- वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, जन मीडिया चैनलों और संचार के नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करना।
- बड़े / केंद्रित पैमाने पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि की पहचान करना।
- वित्तीय साक्षरता संदेशों के सार्थक प्रसार के लिए अधिक विजिबिलिटी (जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आदि) वाले सार्वजनिक स्थलों का लाभ लिया जाना।

सहयोग

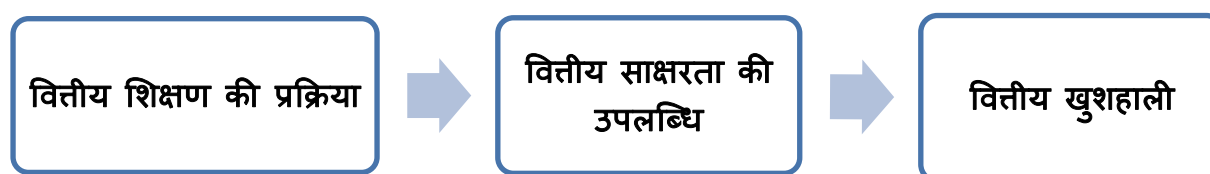
- एक सूचना डैशबोर्ड का निर्माण।
- स्कूली पाठ्यक्रम, बी.एड./एम.एड. कार्यक्रमों की तरह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीएवंई) द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से कराये जा रहे विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वित्तीय शिक्षा सामग्री को एकीकृत करना।
- विभिन्न ऑन-गोइंग कार्यक्रमों के भाग के रूप में वित्तीय शिक्षण प्रसार को एकीकृत करना।
- वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना।

यह दस्तावेज़, कार्यनीति के तहत की गई प्रगति का आंकलन करने के लिए एक मजबूत 'निगरानी और मूल्यांकन ढाँचे' को अपनाने का भी सुझाव देती है।

अध्याय 1: परिचय

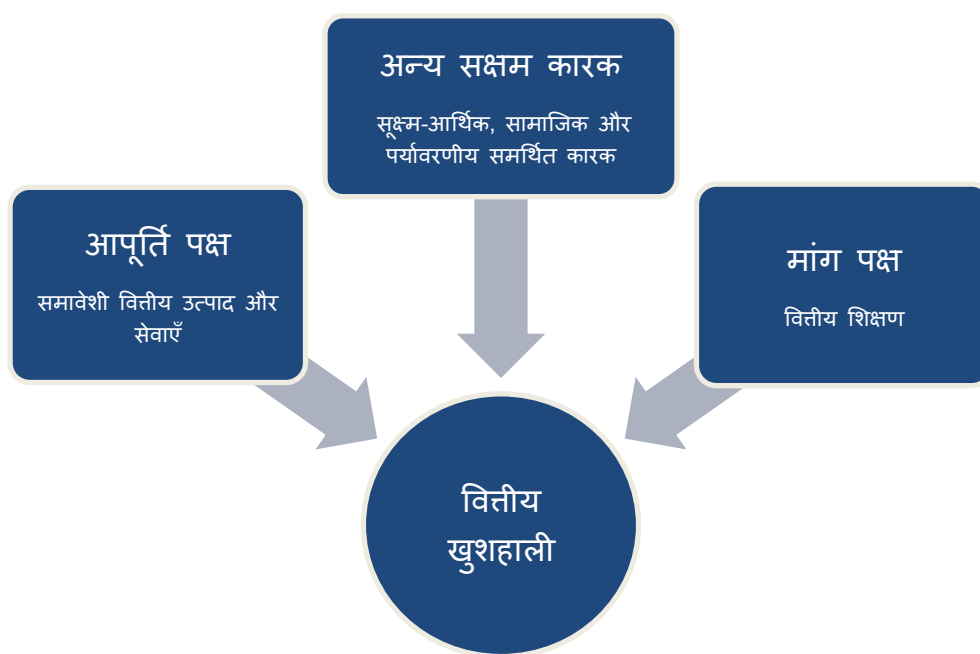
1.1 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षण को परिभाषित करता है। **वित्तीय साक्षरता** को वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है ताकि अंततः व्यक्तिगत वित्तीय खुशहाली की प्राप्ति की जा सके (ओईसीडी, 2012)। दूसरी ओर **वित्तीय शिक्षण** को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता / निवेशक, वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों के बारे में अपनी जानकारी में सुधार करते हैं और सूचना, अनुदेशों और / या उद्देश्यपूर्ण सलाह के माध्यम से सही विकल्प चुनते हैं तथा यह जानने के लिए कि मदद के लिए कहां जाना है तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें कौन से अन्य प्रभावी कार्रवाई करने हैं, वित्तीय जोखिम और अवसरों के बारे में और अधिक जागरूक होने के लिए कौशल और आत्मविश्वास विकसित करते हैं" (ओईसीडी, 2005)।

1.2 जैसा कि देखा जा सकता है, वित्तीय शिक्षण और वित्तीय साक्षरता एक ही टर्म नहीं हैं, ये संबंधित अवधारणाएं हैं। लोग वित्तीय शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं। वित्तीय साक्षरता की उपलब्धि उपयोगकर्ताओं को सही वित्तीय निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाती है जिससे उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति मजबूत होती है।



1.3 भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इस क्षेत्र का विस्तार भी काफी हुआ है। अतः बैंकिंग के विस्तार के साथ-साथ अन्य वित्तीय क्षेत्रों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन विकासों का लाभ आम जनता तक पहुंचे। वित्तीय समावेशन भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) की एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है क्योंकि यह समावेशी विकास हेतु एक प्रमुख प्रवर्तक है। भारतीय संदर्भ में, वित्तीय समावेशन, मुख्यधारा के संस्थागत प्रतिभागियों द्वारा उचित और पारदर्शी तरीके से किरायाती लागत पर कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे असुरक्षित समूहों के लिए आवश्यक उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने

की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन, औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकरण के लिए गरीबों को एक राह प्रदान करता है। जहां वित्तीय समावेशन वास्तव में एक आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप है, वहीं वित्तीय शिक्षण एक मांग पक्ष हस्तक्षेप है। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष पर परिचालित इन घटकों के अलावा, जमीनी स्तर पर अन्य सक्षम कारक भी उपस्थित हैं। किसी भी देश के नागरिकों की वित्तीय खुशहाली से संबंधित उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि ये कारक और बल कितने एकीकृत हैं और ये किस हद तक सामंजस्य में कार्य करते हैं।



1.4 वित्तीय शिक्षण, आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों के द्वारा किए गए पहलों की प्रतिक्रिया में मांग सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबंधित हितधारकों द्वारा वित्तीय शिक्षण पहल लोगों को विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच कर वित्तीय खुशहाली प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन प्रयासों को वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) द्वारा निर्देशित किया जाएगा। प्रसंगवश, वित्तीय शिक्षण, शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सं.4 की उपलब्धि को भी समर्थित करती है जिसका उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा

देना है (शिक्षा पर एसडीजी 4 के तहत साक्षरता पर एसडीजी लक्ष्य 4.6 और जीवन कौशल पर एसडीजी लक्ष्य 4.4)।

1.5 भारत ने पिछले कई वर्षों में अपने नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए अद्भुत प्रगति की है। चूंकि भारत का पहला एनएसएफई 2013 में जारी किया गया था, अतः उस समय से अबतक देश के वित्तीय समावेशन परिदृश्य में कई बदलाव हुए हैं। इस अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन पहलों ने वित्तीय समावेशन परिदृश्य को बदल दिया है। ये पहले अपवर्जित वर्गों को न केवल वित्तीय मुख्य धारा में ला रही हैं, बल्कि ये अपवर्जित वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), आवश्यकता आधारित ऋण, विप्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन तक पहुँच भी सुनिश्चित कर रही हैं।

1.6 विश्व बैंक की नवीनतम फिंडेक्स 2017 रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि देश में औपचारिक खाते वाले वयस्कों का अनुपात 2011 में 35% था जो 2014 में बढ़कर 53% हो गया और 2017 में बढ़कर 80% हो गया। भारत ने खाते के स्वामित्व में देश के लिंगानुपात के अंतर को कम करने में भी असाधारण प्रगति की है, यह 2014 में लगभग 20% था जो 2017 में घटकर 6% हो गया (विश्व बैंक समूह, 2018)। इन सुधारों में से अधिकांश वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार की प्रमुख पहल, अर्थात् पीएमजेडीवाई³, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा निर्मित

³ प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), जिसे अगस्त 2014 में शुरू किया गया था, देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन को लाने के लिए वित्तीय समावेशन पर एक एकीकृत दृष्टिकोण युक्त राष्ट्रीय मिशन है। योजना में, हर घर तक कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुँच के साथ यूनिवर्सल बैंकिंग की परिकल्पना की गई है। यह योजना लाभार्थियों के खातों में सभी सरकारी लाभों (केंद्र / राज्य / स्थानीय निकाय से) को प्रदान करने और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की भी परिकल्पना करती है। इसके उपरान्त, सरकार ने अगस्त 2018 के बाद भी वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन (पीएमजेडीवाई) को जारी रखने का फैसला किया, जिसमें हर घर से प्रत्येक वयस्क के लिए खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब तक पीएमजेडीवाई के तहत 37.70 करोड़ बैंक खाते (18 दिसंबर 2019 को) खोले गए हैं। अधिक जानकारी के लिए <http://www.pmjdy.gov.in/> को देखें।

अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित, का परिणाम माना जा सकता है। वित्तीय समावेशन प्रयासों के माध्यम से प्राप्त लाभों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय साक्षरता को यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभानी होगी कि लोग अपनी वित्तीय खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करें (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2019)।

पृष्ठभूमि और एनएसएफई का औचित्य

1.7 भारत में वयस्क⁴ की एक बड़ी आबादी है। स्पंदनशील और स्थिर वित्तीय प्रणाली के माध्यम से समावेशी विकास पर जोर देते हुये यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत त्वरित गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने, इस जनसांख्यिकीय सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। चूंकि केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, वित्तीय संस्थानों, सिविल सोसाइटियों, शिक्षाविदों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों और अन्य सहित कई हितधारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रसारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे मिलकर कार्य करें तथा उनके कार्य को अन्य उद्देश्यों से इतर पूर्णरूपेण वित्तीय शिक्षण पर समग्र रणनीति से संरेखित करने के लिए, वित्तीय शिक्षण हेतु व्यापक राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) एक पूर्व-आवश्यकता है। हाल के वर्षों में, यह तेजी से पहचाना जा रहा है कि राष्ट्र-व्यापी वित्तीय साक्षरता केवल एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसमें विभिन्न हितधारकों, अर्थात् सरकार, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में), आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है।

1.8 वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को "वित्तीय शिक्षण हेतु एक राष्ट्रीकृत रूप से समन्वित दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक अनुकूलित रूपरेखा या कार्यक्रम समाहित रहता है" (ओईसीडी, 2019)। एनएसएफई दस्तावेज़ का उद्देश्य, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए सक्षम बनाना है जो कि उनके धन के बेहतर प्रबंधन और भविष्य की योजना को निर्मित करने के लिए आवश्यक हैं, भारत सरकार और

⁴ भारत की जनसंख्या 29 अक्टूबर 2019 तक 1,370,862,591 है, जो नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटा के वर्ल्डोमीटर विस्तार पर आधारित है। आयु समूह (15-64), कुल जनसंख्या का 67.27% हिस्सा है और औसत आयु 27.1 (<https://www.worldometers.info/world-population/india-population/>) है।

वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विजन को समर्थित करना है। दस्तावेज़ विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए वर्तमान कार्यों को भी देखता है और भारतीयों की वित्तीय खुशहाली के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाता है।

1.9 इस उद्देश्य के लिए, बुनियादी वित्तीय शिक्षण शुरू करने और देश में आम जनता के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सामग्री विकसित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) को एक धारा (8) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।

1.10 पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है जिसने काफी ऐसे नए अवसरों को सामने लाया है जो अबतक ओझल थे। इस डिजिटल क्रांति को डिजिटल इंडिया कैंपेन, डिजिटल साक्षरता अभियान, आदि द्वारा समर्थित किया गया है। देश में डिजिटल लेनदेन और भुगतान बुनियादी ढांचे में एक प्रतिमान विस्थापन हुआ है (कम नकद उपयोग वाले अर्थव्यवस्था का लक्ष्य)। इन सभी विकासों के कारण, वित्तीय शिक्षण हेतु मौजूदा राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) को संशोधित करना और इसे लागू करने के लिए नवोन्मेषी उपायों को अपनाना अनिवार्य हो गया है। वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (2020-2025) अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता के प्रसार में शामिल वित्तीय सेवा प्रदाताओं एवं अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं के कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करती है।

1.11 यह परिकल्पना की गई है कि इस कार्यनीति को लागू करने से यह देश भर में वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी तथा इस दस्तावेज़ में निर्धारित कार्यनीतिक उद्देश्यों से आबादी के बीच सकारात्मक व्यवहार के परिणाम सामने आएंगे।

अध्याय 2: प्रथम एनएसएफई के तहत प्रगति का अवलोकन (2013-2018)

2.1 2013 में वित्तीय शिक्षण हेतु पहली राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) के आरंभ के बाद से, विभिन्न हितधारकों ने देश की आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई पहलों का एक स्नैपशॉट अनुबंध में प्रस्तुत है। पहली एनएसएफई (2013-2018) के दौरान कार्यान्वित वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रमों से प्राप्त महत्वपूर्ण सीख निम्नानुसार प्रस्तुत है:

- i. **लक्ष्य विशिष्ट मॉड्यूल:** वित्तीय साक्षरता प्रदान करने में सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण से इष्टतम परिणाम प्राप्त नहीं हुये, अतः वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रभावी प्रसार के लिए लक्ष्य विशिष्ट मॉड्यूल विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
- ii. **प्रासंगिक और स्थानीय भाषा दृष्टिकोण:** वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रसार की भाषा और विधा को लक्षित श्रोताओं की भाषा के अनुसार होना चाहिए जिसे समझने में आसानी हो। उदाहरण के लिए, नुक्कड़ नाटक (स्थानीय भाषाओं में नुक्कड़ नाटक) को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना गया था।
- iii. **माध्यम और वितरण का तरीका:** मल्टी-मीडिया साधन जैसे ऑडियो-विजुअल, डिजिटल वैन (गाड़ियों के माध्यम से डिजिटल वित्तीय साक्षरता), डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, कियोस्क, आदि को डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु सबसे बढ़ियां उपकरण माना गया है। वितरण के तरीके के संबंध में, वन-टू-वन लर्निंग और समूह प्रशिक्षण को वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रसार के प्रभावी तरीके के रूप में पाया गया है।
- iv. **कार्य करते हुये सीखना और पीयर-टू-पीयर लर्निंग:** संदेशों की पुनरावृत्ति के अलावा व्यावहारिक अभ्यास / प्रदर्शन के साथ सीखना लंबे समय तक स्थायी रहता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल वैन (डिजिटल वैन) का उपयोग करके डिजिटल वित्तीय लेनदेन के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, आदि।
- v. **जन मीडिया आउटरीच में प्रभावकारिता:** जन मीडिया अभियानों के बीच, प्रसारण के अन्य तरीकों की तुलना में टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित संदेशों को दर्शकों द्वारा अधिक समय के लिए याद रखा जाता है।
- vi. **हितधारक सहयोग को तर्कसंगत बनाना:** वित्तीय शिक्षण के सभी हितधारकों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आरबीआई वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफए) की अवधारणा का प्रयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के वितरण के लिए अभिनव चैनलों का पता लगाने हेतु बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों के सामर्थ्य का लाभ उठाना है। इसी तरह, सेबी वित्तीय

साक्षरता के वितरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीओं के सहयोग से निवेशक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

- vii. **संबंधित उदाहरणों का उपयोग:** वित्तीय साक्षरता संदेश जब वास्तविक जीवन की घटनाओं (जैसे शादी, पालन-पोषण, सेवानिवृत्ति योजना, परिसंपत्ति अधिग्रहण) के साथ जुड़े होते हैं, तो वे विभिन्न लक्षित श्रोताओं के अधिक नजदीक होते हैं।
- viii. **सकारात्मक व्यवहार परिणामों का निर्माण:** वित्तीय शिक्षण कार्यक्रमों से सकारात्मक व्यवहार परिणाम की उत्पत्ति को समझने हेतु और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- ix. **डिजिटल बेस का विस्तार:** डिजिटल वित्तीय सेवाओं में प्रगति की तीव्र गति को देखते हुए, सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रथाओं पर ज्ञान को मजबूत करने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।

ऊपर दी गई प्रमुख बातें, कार्यनीतिक उद्देश्यों (अध्याय 4), नीति निर्माण (अध्याय 5), और कार्य-योजना (अध्याय 6) में शामिल की गई हैं।

बॉक्स आइटम 1: कार्य करते हुये सीखना

मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ; मैं देखता हूँ और मुझे याद रहता है; मैं कार्य करता हूँ और मैं समझता हूँ।

उपरोक्त उद्धरण सीखने के संदर्भ में प्रासंगिक है। यह सर्वविदित है कि किसी भी वित्तीय शिक्षण के हस्तक्षेप का लक्ष्य लक्षित श्रोताओं के बीच वांछनीय वित्तीय व्यवहार के माध्यम से वित्तीय खुशहाली को समर्थित करना है। अतीत में, वित्तीय साक्षरता अभियानों में सामग्री के विकास, प्रतिभागियों के ज्ञान और दृष्टिकोण को बेहतर बनाने पर बहुत से प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। इन वर्षों में, कियोस्क और अन्य स्रोतों के रूप में प्रदर्शन और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के लिए अपनाए गए विभिन्न पहलों में, नुक्कड़ नाटक, नाटकीयता और प्रदर्शन के तरीकों को लक्षित श्रोताओं द्वारा सर्वाधिक सराहा गया है। उदाहरण के लिए, एटीएम से लैस मोबाइल डेमो वैन, माइक्रो-एटीएम, सेबी के रिसोर्स पर्सन और वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी), बैंकों के काउंसलर, दिशानिर्देश के तहत पहली बार दूरदराज के गांवों में डिजिटल लेनदेन करने हेतु व्यक्तियों को सक्षम बना रहे हैं। डिजिटल लेनदेन करके सीखने का यह तरीका ग्रामीण लोगों में से डर को दूर भगा रहा है और उन्हें अधिक डिजिटल लेनदेन करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा मॉड्यूल को एकीकृत करने के प्रयासों के साथ ही सह-शैक्षिक दृष्टिकोण के माध्यम से पाठ्यक्रम कार्यक्रम को पूरक बनाने की भी आवश्यकता है, जिसमें बच्चों को ऐसे प्रासंगिक गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो बेहतर जुड़ाव और बेहतर प्रतिधारण परिणाम की क्षमता रखता हो। एनसीएफई का मनी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम स्कूली छात्रों को एक प्रमुख जीवन कौशल के रूप में अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने और उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने हेतु प्रोत्साहित करता है। सभी वित्तीय शिक्षण पहलों का लक्ष्य है कि छात्रों में विभिन्न अवधारणाओं के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने हेतु पुनरावृत्तियों के माध्यम से व्यावहारिक पहलुओं को शामिल करना चाहिए।

अध्याय 3: आवश्यकताओं का आंकलन और महत्वपूर्ण अंतर

3.1 लोगों की जरूरतों और देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक व्यापक कार्यनीति तैयार करने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया को भारतीय संदर्भ में अपनाया गया है:

क). वित्तीय साक्षरता में अंतर का आंकलन और मूल्यांकन।

ख). ओईसीडी-आईएनएफई क्रॉस-कंट्री फ्रेमवर्क के मानदंडों के आधार पर एनएसएफई की तुलना।

क). वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतर का आंकलन और मूल्यांकन

3.2 एनसीएफई ने भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने के लिए एक बाहरी सर्वेक्षण एजेंसी की मदद से 2019 में एक अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण को पूरा किया है। यह उल्लेखित है कि ओईसीडी-आईएनएफई टूल किट की तर्ज पर 2013 में भी इसी तरह का एक सर्वेक्षण किया गया था। 14 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय भाषाओं में घरेलू प्रश्नावली के सेट का उपयोग करके 18 से 79 वर्ष की आयु के 75000 वयस्कों का नमूना लिया गया था। सर्वेक्षण के दौरान जिलों, ब्लॉक / वार्डों, गांवों, घरों, उत्तरदाताओं के चयन के लिए एक बहु-चरण नमूनाकरण तकनीक अपनाया गया है।

बॉक्स आइटम 2: वित्तीय साक्षरता के घटकों की ओईसीडी-आईएनएफई परिभाषा

वित्तीय साक्षरता में धन प्रबंधन, अल्प और दीर्घावधि वित्तीय लक्ष्यों की योजना और जागरूकता तथा वित्तीय उत्पादों के विकल्प के संदर्भ में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार के पहलुओं को समाहित किया गया है।

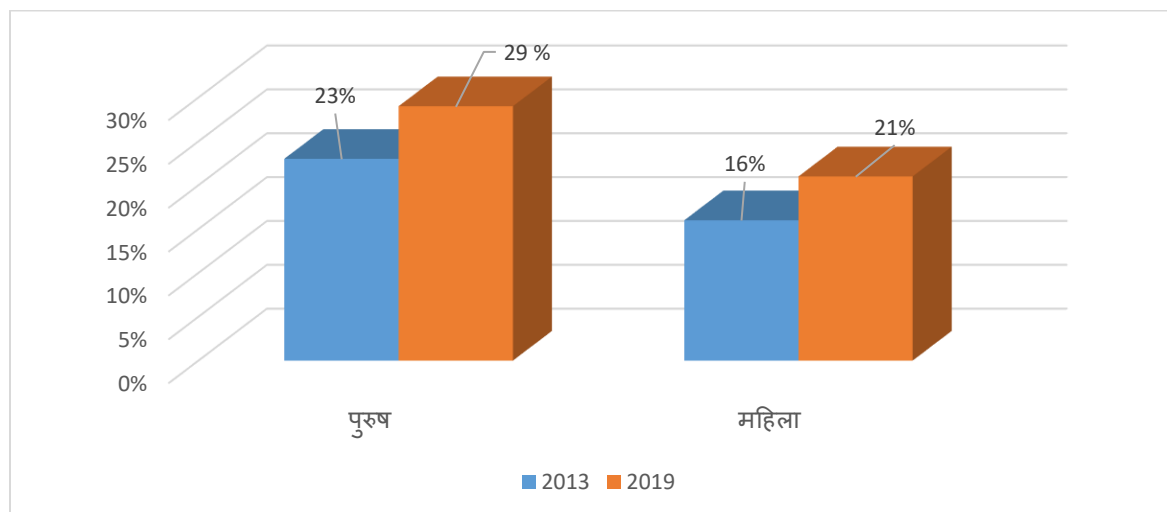
वित्तीय ज्ञान में प्रमुख वित्तीय अवधारणाओं की समझ और वास्तविक जीवन की वित्तीय स्थितियों में लाभ का मूल्यांकन करने की क्षमता शामिल है। किसी व्यक्ति के वित्तीय ज्ञान का निर्धारण करने के लिए सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मुद्रा का आवधिक मूल्य, मुद्रास्फीति, विविधीकरण, विभाजन, जोखिम-प्रतिफल और ऋण पर दिए गए ब्याज की अवधारणा का परीक्षण किया जाता है।

वित्तीय व्यवहार में दिन-प्रतिदिन के धन प्रबंधन, वित्तीय योजना, खर्च, बचत, निवेश, दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण पर निर्भरता और बेहतर भविष्य हेतु सुरक्षा उपायों के निर्माण का अध्ययन शामिल

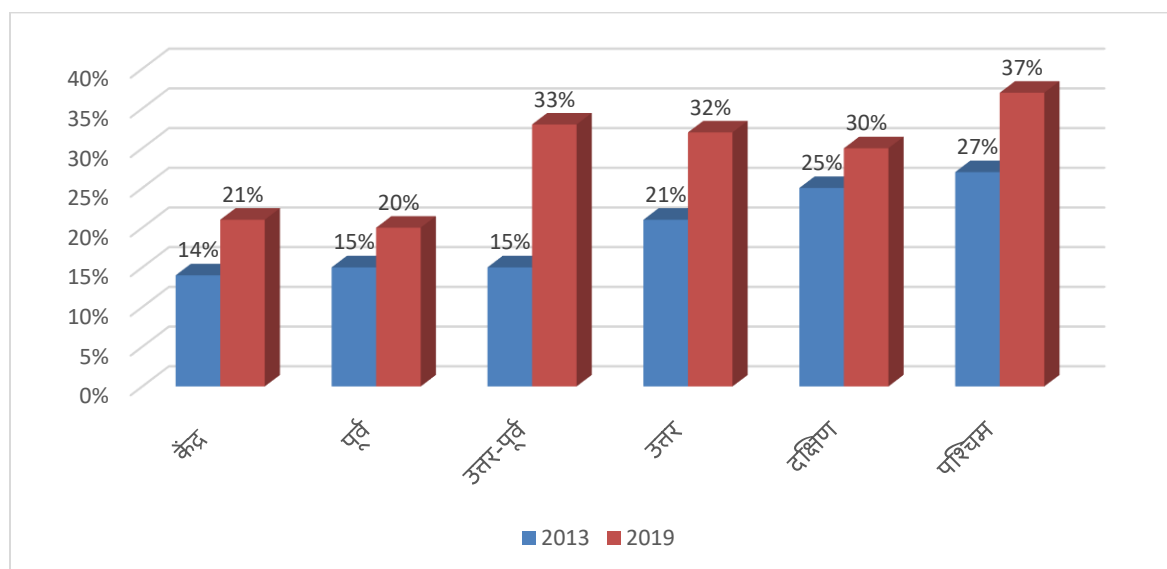
3.3 2019 में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि ओईसीडी-आईएनएफई द्वारा निर्धारित वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटकों में से न्यूनतम लक्ष्य स्कोर / न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर [अर्थात् वित्तीय मनोवृत्ति में न्यूनतम 3 (5 में से), वित्तीय व्यवहार में 6 (9 में से) और वित्तीय ज्ञान में 6 (9 में से)] के अंतर्गत उत्तरदाताओं ने वर्ष 2013 के 20% की तुलना में 2019 में 27.18% स्कोर प्राप्त किया है।

3.4 सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत किए गए हैं:

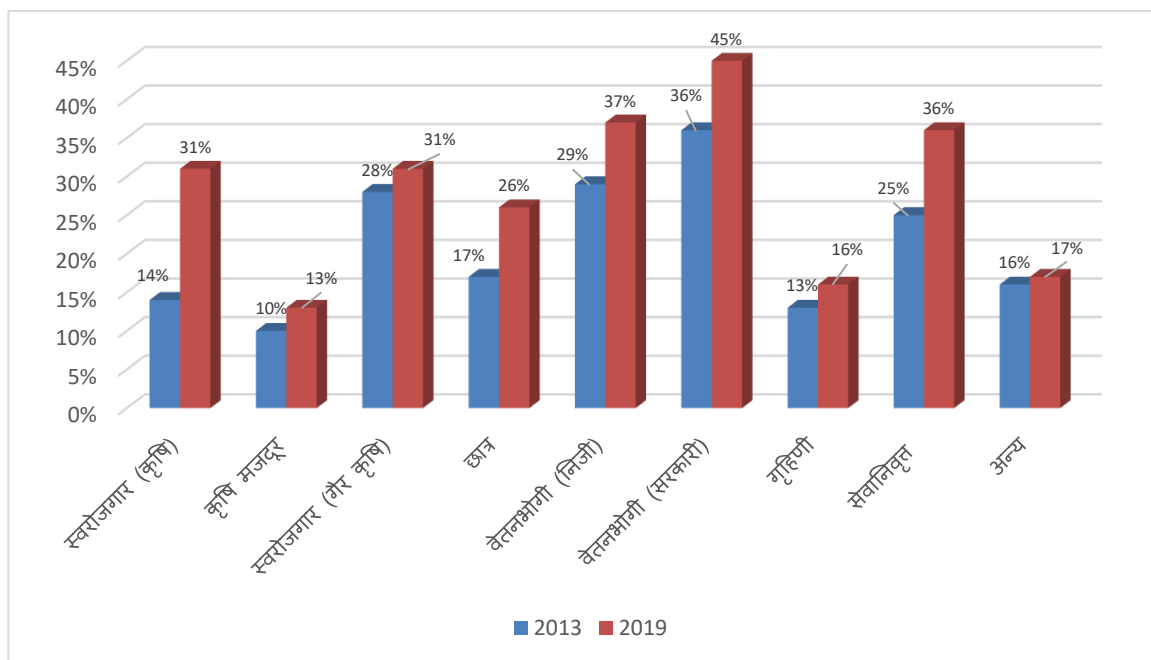
चार्ट 1: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का लिंग-वार प्रतिशत



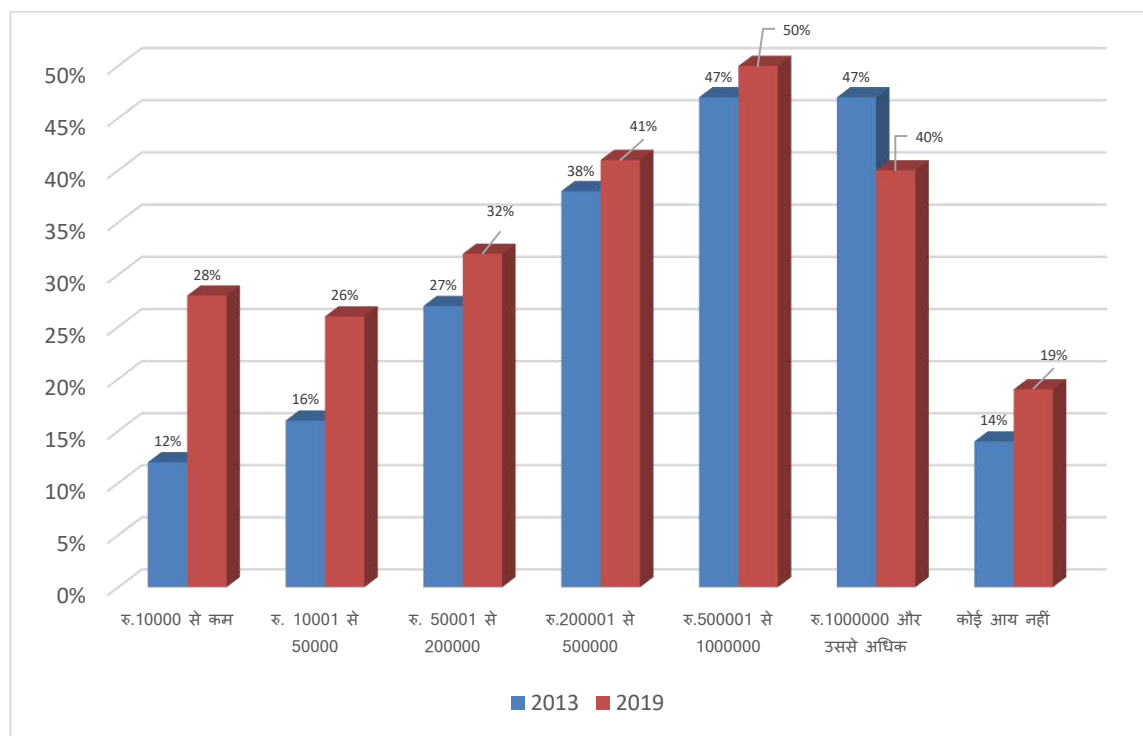
चार्ट 2: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का क्षेत्र-वार प्रतिशत



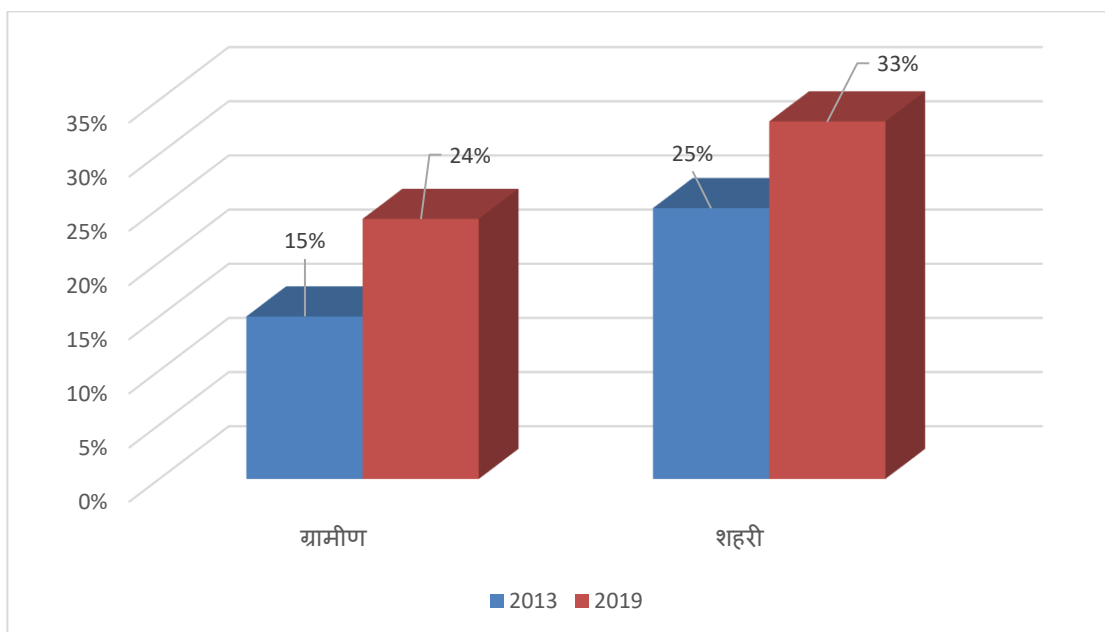
चार्ट 3: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का उपजीविका-वार प्रतिशत



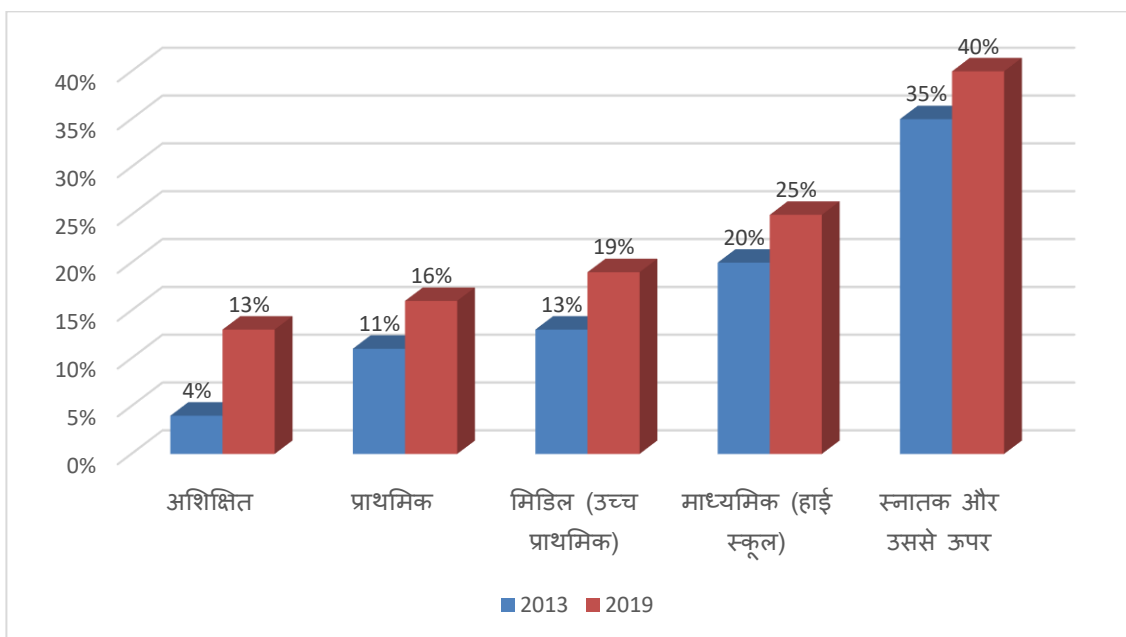
चार्ट 4: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का वार्षिक आय-वार प्रतिशत



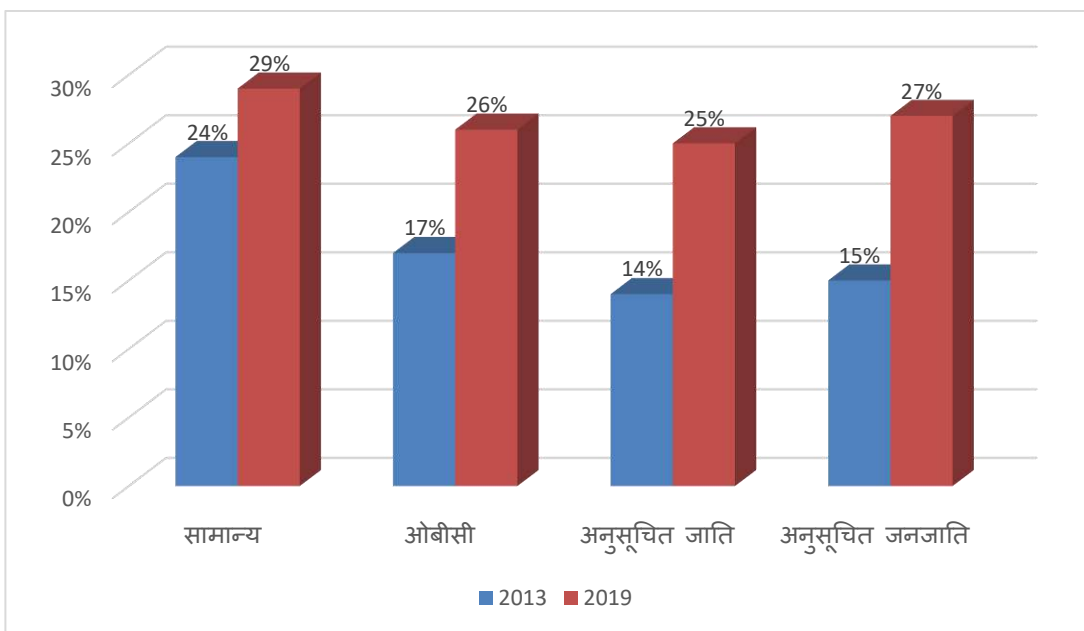
चार्ट 5: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का ग्रामीण-शहरी प्रतिशत



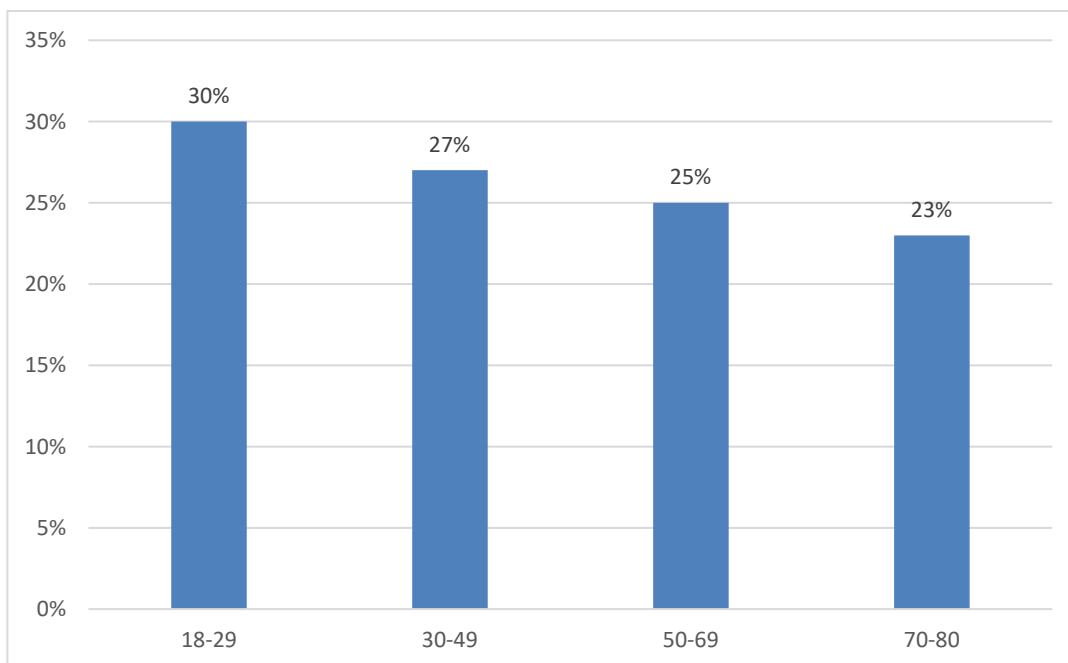
चार्ट 6: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का शिक्षा-वार प्रतिशत



चार्ट 7: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का सामाजिक श्रेणी-वार प्रतिशत



चार्ट 8: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का आयु-वार प्रतिशत (2019)



3.5 उपरोक्त उदाहरण चार्ट के आधार पर, वित्तीय शिक्षण प्रयासों में सुधार के लिए निम्नलिखित महत्व वाले क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं:

- i. यद्यपि हाल के वर्षों में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है
- ii. पूर्व, मध्य और उत्तर क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है⁵
- iii. ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है
- iv. निम्न शिक्षा वाले समूह के लिए अधिक वित्तीय शिक्षण के पहल की आवश्यकता है
- v. '50 और उससे अधिक आयु' के समूह को अधिक वित्तीय शिक्षण की आवश्यकता है

ख). वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर ओईसीडी-आईएनएफई की नीति पुस्तिका के साथ एनएसएफई की तुलना

3.6 वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर ओईसीडी-आईएनएफई की नीति पुस्तिका (ओईसीडी, 2015), राष्ट्रों को वित्तीय शिक्षण हेतु अपनी राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण व व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। पुस्तिका के आधार पर, देश की कार्यनीति विकसित करने के लिए भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित पहलू को अपनाया गया है:

1. मूल्यांकन के साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यनीति की नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान

क). मौजूदा पहलों का मैपिंग अभ्यास : वित्तीय शिक्षण हेतु पहली राष्ट्रीय कार्यनीति (2013-2018) की शुरुआत के बाद से पिछले पांच वर्षों की प्रगतियों और देश की उभरती आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एनसीएफई ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक; बैंकों; विकास वित्त संस्थानों; भारतीय बैंक संघ; स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) (एफआईडीसी, एम-फिन और सा-धन); और अन्य हितधारकों (जैसे एनपीसीआई) के परामर्श से मौजूदा पहलों का एक मैपिंग अभ्यास किया था। एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, विकास वित्त संस्थानों, एनपीसीआई आदि द्वारा की गई प्रमुख पहलों को अनुबंध में संक्षेपित

⁵2013 में किए गए सर्वेक्षण में, उत्तर-पूर्व क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र के तहत शामिल किया गया था। अतः 2013 और 2019 के बीच उत्तर-पूर्व डेटा की तुलना नहीं हो सकती है।

किया गया है। कार्यनीतिक उद्देश्यों को तैयार करने और कार्य-योजनाओं को विकसित करने में वित्तीय शिक्षण पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अध्ययन के साथ इन पहलों से महत्वपूर्ण सीख का उपयोग किया गया है।

ख). **राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और समावेशन के स्तर का मापन:** देश में वित्तीय साक्षरता के स्तर का आंकलन करने के लिए ओईसीडी-आईएनएफई टूलकिट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप 2013-2014 में एक अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण संचालित किया गया था। पहले एनएसएफई की अवधि के पूरा होने के उपरांत, पिछले पांच वर्षों (2013-2018) के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 2019 में एक सर्वेक्षण संचालित किया गया है।

II. संस्थागत और शासी व्यवस्था की स्थापना

कार्यनीति के मार्गदर्शन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, एक सुपरिभाषित संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है और उसे अध्याय 6 में प्रस्तुत किया गया है।

III. वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति की मूल्यांकन योजना

कार्यनीति की अवधि के तहत विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक मानकीकृत विधि अध्याय 7 में प्रस्तुत की गई है।

अध्याय 4: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025)

4.1 जैसा कि एडवांसिंग नेशनल स्ट्रेटिजी फॉर फ़िनान्सिअल एडुकेशन नामक शीर्षक दस्तावेज़ (ओईसीडी और रूस की जी 20 प्रेसीडेंसी द्वारा 2003 में संयुक्त रूप से प्रकाशित) में उल्लेखित है - वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक संस्थानों द्वारा विकसित किए जाने वाले स्पष्ट वित्तीय शिक्षण आदेशों, उद्देश्यों और संसाधनों को स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है।

4.2 इस कार्यनीति दस्तावेज़ को पहले एनएसएफई (2013-2018) के संशोधित संस्करण के रूप में विकसित किया गया है जिसमें डेटा-चालित निष्कर्ष, नए नीतिगत उपाय, मूल्यांकन उपकरण, हस्तक्षेप और तकनीकी सुधार शामिल हैं। चूंकि यह कार्यनीति पहले के कार्यनीति का संशोधन है, अतः विज़न को बनाए रखने और मिशन को निम्नलिखित कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है।

विजन - आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत

4.3 चूंकि वित्तीय समावेशन परिदृश्य और सामान्यतः अर्थव्यवस्था में कई विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं, अतः वृहद आर्थिक परिदृश्य में हुये परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने और विविधता से भरे इस विशाल देश में वित्तीय शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कार्यनीतिक उद्देश्यों को संशोधित किया गया है।

कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- i. वित्तीय शिक्षण के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों को वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को आत्मसात करने एवं उसे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए प्रेरित करना
- ii. सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना
- iii. वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- iv. क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और आवश्यकतानुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना
- v. सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना
- vi. प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना

- vii. उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना
- viii. अधिकारों, कर्तव्यों और शिकायत निवारण के लिए माध्यमों के बारे में जानकारी
- ix. वित्तीय शिक्षण में प्रगति का आंकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार

4.4 ग्रैन्युलैरिटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय शिक्षण हेतु सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण से हमें वांछित सफलता न मिलने की सीख के आधार पर, कार्यनीतिक उद्देश्यों को निम्नलिखित आयामों के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है:

क्र.सं.	आयाम	संक्षिप्त विवरण
1	लक्ष्य श्रोता का जीवन स्तर	बच्चे, युवा वयस्क, कार्यस्थल के वयस्क, वरिष्ठ नागरिक-महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना
2	असुरक्षित सामाजिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वृहत भू-भाग	असुरक्षित सामाजिक समूहों, प्रवासियों, निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण, शहरी (शहरी गरीबों और प्रवासियों पर ध्यान देने के साथ), आकांक्षी जिले, एलडब्लूई, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), पहाड़ी राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप
3	क्षेत्र विशिष्ट फोकस	कृषि, विनिर्माण (एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत कुशल / अकुशल श्रमिक / कारीगर, स्वयं सहायता समूह के सदस्य), स्व-नियोजित / असंगठित क्षेत्र

4.5 वित्तीय शिक्षण के प्रसार हेतु प्रासंगिक **सामग्री** (स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम सहित) के विकास, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच **क्षमता** का विकास, उपयुक्त **संचार** कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए **सामुदायिक** नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाने, और अंत में विभिन्न हितधारकों के बीच **सहयोग** बढ़ाने पर बल देने के साथ **'5 सी'** दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।

आकृति 1: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025)

वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (2020-2025)

विजन

आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत

कार्यनीतिक उद्देश्य

- i. वित्तीय शिक्षण के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों को वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को आत्मसात करने एवं उसे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए प्रेरित करना
- ii. सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना
- iii. वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- iv. क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और आवश्यकतानुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना
- v. सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना
- vi. प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना
- vii. उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना
- viii. अधिकारों, कर्तव्यों और शिकायत निवारण के लिए माध्यमों के बारे में जानकारी
- ix. वित्तीय शिक्षण में प्रगति का आंकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार

आयाम 1
लक्ष्य श्रोता का जीवन स्तर
(महिलाओं पर विशेष ध्यान)

बच्चे

युवा वयस्क

कार्यस्थल के
वयस्क

वरिष्ठ नागरिक

आयाम 2
असुरक्षित सामाजिक समूहों पर ध्यान
केंद्रित करने के साथ वृहत भू-भाग

ग्रामीण
क्षेत्र

आकांक्षी जिले, एलडब्ल्यूई,
एनईआर, पहाड़ी राज्य

शहरी गरीबों और प्रवासियों पर
ध्यान केंद्रित करने के साथ
शहरी क्षेत्र

आयाम 3
अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान
केंद्रित करने के साथ आर्थिक
क्षेत्र

लघु और सीमांत किसानों
पर ध्यान केंद्रित करने
के साथ कृषि

असंगठित क्षेत्र में कुशल / अकुशल
श्रमिकों / कारीगरों पर ध्यान केंद्रित
करने के साथ एमएसएमई क्षेत्र

एसएचजी
(स्वयं सहायता
समूह)

5 सी

सामग्री

क्षमता

सामुदायिक

संचार

सहयोग

अध्याय 5 : नीति निर्माण

5.1 वित्तीय शिक्षण के घटक

5.1.1 बुनियादी वित्तीय शिक्षण

बुनियादी वित्तीय शिक्षण में वित्तीय खुशहाली के मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं⁶। मुद्रा योजना के अलावा एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के साथ सरकार की पीएमजेडीवाई योजना आरंभ होने से कई लोगों को पहले ही इसमें शामिल किया जा चुका है। उन्हें वित्तीय शिक्षण की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। इन बुनियादी अवधारणाओं को, जो कि लक्षित श्रोताओं के लिए उपयुक्त हो, वितरण के विभिन्न माध्यमों से सभी को सूचित किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से अपवर्जित और खातों का परिचालन न करने वाले नए लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बुनियादी वित्तीय शिक्षण, क्षेत्र-विशिष्ट और प्रक्रिया शिक्षा के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है।

5.1.2 क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय शिक्षण

वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय शिक्षण प्रदान की जा रही है और वित्तीय सेवाओं के "क्या" तथा सामग्री में 'क्या करें एवं क्या न करें' से संबंधित जागरूकता को कवर करने, 'अधिकार और जिम्मेदारियां', 'डिजिटल वित्तीय सेवाओं का सुरक्षित उपयोग' और 'शिकायत निवारण' प्राधिकरण से संपर्क, पर केंद्रित है।

बुनियादी और क्षेत्र विशिष्ट शिक्षण किसी व्यक्ति को अधिक विवेकपूर्ण होने के लिए सशक्त बनाएगी तथा उपलब्ध विकल्पों में से उनके आवश्यकतानुसार उपयुक्त वित्तीय उत्पादों के चयन हेतु सटीक निर्णय लेने में मदद करेगी।

⁶अवधारणाओं में, (क) बचत के महत्व और फायदे, (ख) अनुत्पादक ऋणों से दूर रहना, (ग) जरूरत और क्षमता के अनुसार औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उधार लेना, (घ) ब्याज दर और चक्रवृद्धि की शक्ति, (ङ) मुद्रा का आवधिक मूल्य, (च) मुद्रास्फीति, (छ) बीमा करने की आवश्यकता, (ज) वृद्धावस्था आय के लिए योजना बनाने की आवश्यकता, (झ) मंत्रालयों, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों और बीमा कंपनियों जैसे प्रमुख वित्तीय क्षेत्र से संबंधित संस्थानों की भूमिका, और (ञ) जोखिम और प्रतिफल के बीच के संबंध के बारे में बुनियादी अवधारणाएं, (ट) शिकायत निवारण, शामिल हैं।

5.1.3 प्रक्रिया शिक्षण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज्ञान, व्यवहार में परिवर्तित हो, प्रक्रिया शिक्षण महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, सम्मिलित किए जाने वाले कुछ पहलुएं निम्नानुसार हैं:

- एटीएम कार्ड का उपयोग कैसे करें?
- यूपीआई लेनदेन कैसे करें?
- बीसी के साथ पैसे कैसे जमा करें?
- ऋण आवेदन पत्र कैसे भरें?
- एक उपयुक्त ऋण उत्पाद की तुलना और चयन कैसे करें?
- बीमा कवर कैसे खरीदें?
- प्रतिभूति बाजारों में विभिन्न लेनदेन कैसे करें?
- पेंशन योजना में फंड कैसे आवंटित करें?
- वित्तीय सेवा प्रदाता के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज करें?
- लोकपाल / शिकायत निवारण प्राधिकरण, आदि से कैसे संपर्क करें?

इन सामग्रियों को आसानी से समझ में आ जानेवाले ऑडियो / वीडियो, एनिमेटेड पोस्टरों के रूप में विकसित किया जाना है ताकि उपभोक्ताओं को विभिन्न लेनदेनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिल सके। (उदाहरण के लिए, एटीएम का उपयोग करने के बारे में एटीएम मशीन में प्रदर्शित एक छोटा वीडियो, ग्राहक के लिए सेवा का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा)

5.2 वित्तीय शिक्षण हेतु वितरण चैनल

वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार हेतु पहले से मौजूद वितरण चैनलों के अलावा, वितरण माध्यमों के नए प्रकार जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सामुदायिक रेडियो, प्रौद्योगिकी कियोस्क, चैटबॉटसेट आदि को प्रभावी ढंग से स्थापित किया जा सकता है।

अध्याय 6: कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना

6.1 प्रासंगिक **सामग्री** के विकास, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच **क्षमता** का विकास, विभिन्न हितधारकों के बीच **सहयोग** बढ़ाने के द्वारा उपयुक्त **संचार** कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए **सामुदायिक** नेतृत्व वाले मॉडल की सुविधाजनक भूमिका का लाभ उठाने पर बल देकर, **5-सी' दृष्टिकोण / 5-मुख्य कार्रवाई** को अपनाया जा सकता है।

नीचे दिये गए प्रत्येक मुख्य कार्रवाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है-

6.1.1 सामग्री

- स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सह-शैक्षिक सहित), शिक्षकों, युवा व्यस्कों, महिलाओं, कार्यस्थल पर आए नए लोगों/ उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री।

6.1.2 क्षमता

- ऐसे विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं के क्षमता को विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु शामिल किए जा सकें
- वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए एक 'आचार संहिता' विकसित करना

6.1.3 सामुदायिक

- धारणीय रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण का निर्माण

6.1.4 संचार

- वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, जन मीडिया चैनलों और संचार के नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करना
- बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि की पहचान करना
- वित्तीय साक्षरता संदेशों के सार्थक प्रसार के लिए अधिक विजिबिलिटी (जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आदि) वाले सार्वजनिक स्थलों का लाभ लिया जाना

6.1.5 सहयोग

- एक सूचना डैशबोर्ड का निर्माण।

- स्कूली पाठ्यक्रम, बी.एड./एम.एड. कार्यक्रमों की तरह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीएवंई) द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से कराये जा रहे विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वित्तीय शिक्षण सामग्री को एकीकृत करना
- विभिन्न ऑन-गोइंग कार्यक्रमों के भाग के रूप में वित्तीय शिक्षण प्रसार को एकीकृत करना
- वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना

6.2 विस्तृत कार्यान्वयन योजना के साथ कार्यनीतिक लक्ष्य एवं माइलस्टोन की जानकारी निम्नलिखित पृष्ठों में प्रस्तुत है-

एनएसएफई के लिए कार्य-योजना (2020-2025)

5 सी	क्र सं	कार्यनीतिक लक्ष्य	कार्यान्वयन योजना	माइलस्टोन	के द्वारा कार्रवाई
सामग्री	1	स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सह-शैक्षिक सहित), शिक्षकों, युवा व्यस्क, महिलाओं, कार्यस्थल पर आए नए लोगो/ उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण	विशिष्ट लक्ष्य ऑडियंस ओरिएंटेशन (जैसे शिक्षक, स्कूली बच्चे, युवा वयस्क, महिलाएं, कार्यस्थल पर आए नए लोगो / वयस्क उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि) के साथ ऐसे सामग्री का निर्माण करना जिसे ऑडियो-वीडियो, प्रिंट, जन मीडिया, डिजिटल प्रारूप आदि के माध्यम से प्रसारित किया जा सके। सामग्री में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय सेवाएं शामिल होंगी, जिसे बेहतर पहुंच को बढ़ावा देने और लक्ष्य श्रोताओं के बीच अपनेपन के साथ अपनाए जाने के लिए स्थानीय वाक्यांशों / बोलियों के सक्रिय समावेश के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए।	मार्च 2021	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक, सिडबी और नाबार्ड
			छूठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण सामग्री को अद्यतन करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री को सुलभ बनाना	मार्च 2021	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और एमएसजेएवंई

			व्यावसायिक शिक्षा (आईटीआई / पॉली-तकनीकी पाठ्यक्रम आदि) के अभिन्न अंग के रूप में वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने और सह-शैक्षिक दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च कक्षाओं (कक्षा XI-XII) के छात्रों के बीच वित्तीय जागरूकता के लिए सामग्री का निर्माण करना	मार्च 2022	एनसीएफई, एमएसडीएवंई और एमएचआरडी
क्षमता	1	ऐसे विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं के क्षमता को विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु शामिल किए जा सकें	वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण साधन बनने के लिए एफएलसी काउंसलर्स, सेबी के रिसोर्स पर्सन, ग्रामीण शाखा प्रबंधक आदि के क्षमता को विकसित करना	मार्च 2022	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			वित्तीय क्षेत्र के नवीनतम घटनाओं के बारे में एनआरएलएम के मास्टर प्रशिक्षकों को अद्यतन करने के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी सक्षमता में सुधार करना	मार्च 2022	एनसीएफई, एमओआरडी और नाबार्ड
			एसएचजी नेतृत्वकर्ताओं, बैंक सखियों की क्षमता को मजबूत करना जो कि वित्तीय साक्षरता के प्रसार में मदद कर सकें	मार्च 2022	एनसीएफई, नाबार्ड, एमओआरडी, आरबीआई और सेबी
			माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों (कक्षा VI-X) की क्षमता को मजबूत करना जो कि वित्तीय साक्षरता सामग्री का प्रसार कर सकें	मार्च 2022	एनसीएफई और एमएचआरडी
	2	वित्तीय शिक्षण प्रदाताओं के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करना	वित्तीय शिक्षण प्रदाताओं के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता विकसित की जाए	मार्च 2021	वित्तीय क्षेत्र के सभी

					विनियामक और एनसीएफई
सामुदायिक	1	धारणीय रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण का निर्माण	वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु एजेंट बनने के लिए स्वयंसेवकों, स्थानीय एसएचजी, फील्ड स्तर के अधिकारियों, शिक्षकों और सामुदायिक दूतों को प्रोत्साहित करने हेतु सामुदायिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को विकसित करना	मार्च 2021	एनसीएफई, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड और राज्य सरकारें
			औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाताओं, बीसी, सीएफएल, एफएलसी, आदि से संपर्क करने के लिए लोगों को जुटाने हेतु एजेंट बनने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, पोस्ट मेन आदि की सेवाओं का उपयोग करना	मार्च 2023	एनसीएफई, आईपीपीबी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
			सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण के अंतर्गत लक्षित अभियानों के माध्यम से देश के अंडरबैंक जिलों और आकांक्षी जिलों में वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम (एफईपीए) आयोजित करना	मार्च 2022	एनसीएफई, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारें
संचार	1	वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, जन मीडिया चैनलों और संचार के	वित्तीय साक्षरता संदेशों को वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के वेबसाइट पर किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			एक वित्तीय साक्षरता मोबाइल ऐप विकसित करना	मार्च 2021	एनसीएफई

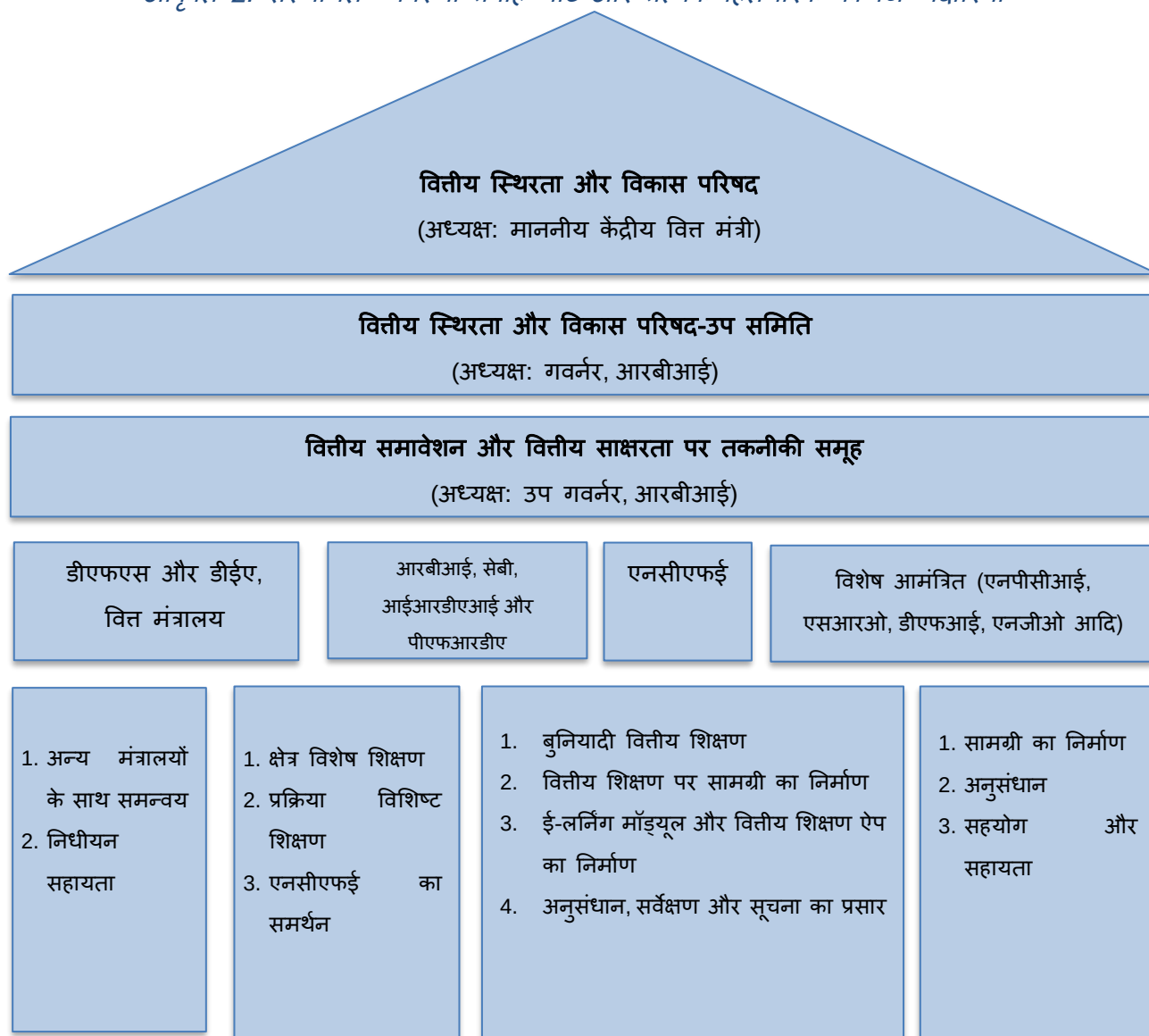
		नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करना	शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक सामान्य टोल-फ्री नंबर विकसित करना	मार्च 2022	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल कियोस्क का लाभ लिया जाना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			वित्तीय शिक्षण पर आम उपभोक्ता प्रश्नों के उत्तर हेतु चैटबॉट्स के विकास का अन्वेषण करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
	2	बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि की पहचान करना	वर्तमान में आरबीआई द्वारा संचालित किए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह की तर्ज पर वर्ष के दौरान एक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			जनता में केंद्रित जागरूकता लाने के लिए वर्ष में एक बार डिजिटल वित्तीय सेवा दिवस मनाया जाना	मार्च 2021	एमईआईटीवाई, एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
	3	वित्तीय साक्षरता संदेशों के सार्थक प्रसार के लिए अधिक विजिबिलिटी (जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आदि) वाले सार्वजनिक स्थलों का लाभ लिया जाना	अधिक विजिबिलिटी वाले विशिष्ट सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, अस्पताल, ग्राम पंचायत कार्यालय, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), बसों और ट्रेनों, आदि, पर प्रासंगिक वित्तीय साक्षरता संदेश प्रदर्शित करना	मार्च 2023	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और सीएसआर गतिविधि संचालित करने वाले कॉरपोरेट्स

सहयोग	1	एक सूचना डैशबोर्ड का निर्माण	विभिन्न हितधारकों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के विवरण से युक्त एक डिजिटल रिपोर्टिरी तैयार करना जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों पर एक सूचना डैशबोर्ड होगा।	मार्च 2021	एनसीएफई
	2	स्कूली पाठ्यक्रम, विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बी.एड./एम.एड. कार्यक्रमों की तरह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीएवंई) द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से आयोजित) में वित्तीय शिक्षा सामग्री को एकीकृत करना	वित्तीय रूप से शिक्षित शिक्षण पेशेवरों का एक केंद्र तैयार करने के लिए अन्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा बी.एड./एम.एड. जैसे पाठ्यक्रमों में वित्तीय शिक्षा को एकीकृत करना	मार्च 2023	एनसीएफई और यूजीसी / एमओएचआरडी
			एमएसडीएवंई द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल को एकीकृत करना	मार्च 2025	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और एमएसडीएवंई
			छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को एकीकृत करना	मार्च 2022	एनसीएफई, एमएचआरडी, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) और राज्य सरकारें
	3	विभिन्न ऑन-गोइंग कार्यक्रमों के भाग के रूप	वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए वित्तीय शिक्षण का वितरण	मार्च 2022	एनसीएफई

		में वित्तीय शिक्षा प्रसार को एकीकृत करना			
	4	वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना	एनसीएफई को वित्तीय शिक्षण प्रदान करने में शामिल सरकारी निकायों के बीच कार्यनीतिक साझेदारी के बारे में अन्वेषण करना है	मार्च 2021	एनसीएफई
			उद्योग संघों, स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) और वित्तीय क्षेत्र के अन्य मध्यस्थों (जैसे आईबीए, एफडीडीआई, एएमएफआई, बीसीएफआई, एमएफआईएन आदि) को वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु भूमिका सौंपी जाए।	मार्च 2022	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के विनियामक

उपरोक्त कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से हस्तक्षेप हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

आकृति 2: संस्थागत व्यवस्था प्रवाह चार्ट और प्रत्येक हितधारक की जिम्मेदारियां



6.3 पिछली कार्यनीति के अनुरूप, वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (2020-2025) के पूरे भाग को संस्थागत प्रणाली, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, के माध्यम से लागू किए जाने की आवश्यकता है। एफएसडीसी (अध्यक्ष: माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री) की निगरानी के अलावा, कार्यनीति के कार्यान्वयन की निगरानी सीधे वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) (अध्यक्ष: उप गवर्नर, आरबीआई) द्वारा की जाएगी।

6.4 चूंकि वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन के बाद से वृहद स्तर पर वित्तीय संसाधनों और श्रमशक्ति के आवंटन एवं तैनाती की आवश्यकता होगी, अतः सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय विनियामकों के स्तर पर भी पर्याप्त आयोजना की आवश्यकता

होगी। वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों, उनके संबंधित विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों को चाहिए कि वे इस हेतु आवश्यक प्रावधान करें।

6.5 राष्ट्रीय कार्यनीति में प्रमुख हितधारकों की पहचान : कार्यनीतिक लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित हितधारकों की पहचान की गई है। सूची उदाहरणार्थ है, परिपूर्ण नहीं।

- i. भारत सरकार: वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी कार्य और गरीबी उपशमन मंत्रालय / राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- ii. वित्तीय क्षेत्र के विनियामक: आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए
- iii. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)
- iv. विकास वित्त संस्थान: नाबार्ड और सिडबी
- v. उद्योग संघ: आईबीए, एएमएफआई, एफईडीएआई, बीसीएफआई
- vi. प्रतिभूति बाजार संस्थागत इन्फ्रास्ट्रक्चर: स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी
- vii. भुगतान संस्थान: एनपीसीआई
- viii. निवेशक शिक्षण संस्थान: आईईपीएफए, आईआईसीए, आदि
- ix. वित्तीय सेवा प्रदाता: बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां, पेंशन फंड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, फिन-टेक कंपनियां, आदि
- x. स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ): एफआईडीसी, एम-फिन, सा-धन, आदि
- xi. सभी राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)
- xii. गैर सरकारी संगठन / सिविल सोसायटी संगठन
- xiii. अनुसंधान संस्थान
- xiv. उपभोक्ता संघ
- xv. मल्टी-लेटरल इंस्टिट्यूशन (ओईसीडी-आईएनएफई, जी20, आदि): वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान साझा करने हेतु

बॉक्स आइटम 3: वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और सिविल सोसायटी

वित्तीय समावेशन में सुधार हेतु पीएमजेडीवाई और पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई (सूक्ष्म-बीमा), पीएमजेडीवाई (सूक्ष्म-ऋण) का ओवर-ड्राफ्ट (ओडी) और मुद्रा योजना (एमएसएमई / गैर-कृषि ऋण) तथा एपीवाई (सूक्ष्म पेंशन), सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिससे एक समतामूलक समाज का निर्माण होता है। यह सर्वविदित है कि वित्तीय समावेशन प्रयासों के माध्यम से खोले गए खातों का उपयोग लोगों द्वारा उनके लिए प्रासंगिक उत्पादों / सेवाओं का लाभ उठाकर किया जा रहा है, को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय साक्षरता एक प्रमुख साधन है। वित्तीय साक्षरता में व्याप्त अंतर को पाटने के लिए, विभिन्न हितधारकों के बीच उनकी व्यक्तिगत मुख्य सक्षमताओं के आधार पर कार्यनीतिक साझेदारी का अन्वेषण किए जाने की नितांत आवश्यकता है। इस मामले में प्रौद्योगिकी कंपनियों (फिन-टेक) और लोकोपकारी संगठनों / सिविल सोसाइटी के बीच संभावित सहयोग की आवश्यकता है, जो विभिन्न लक्षित श्रोताओं (उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों, आकांक्षी जिलों में युवाओं और एलडब्लूई जिलों में महिलाओं) के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु अपने प्रयासों में तालमेल बिठा सकें। हालांकि इस सामग्री के व्यापक रूप को प्रमुखता से प्रसारित किया जा सकता है, परंतु स्थानीय एनजीओ, जिन्हें समुदायों की जमीनी वास्तविकताओं का अच्छा ज्ञान होता है, इसे अनुकूलित कर सकते हैं और इसे लक्षित श्रोताओं के लिए प्रासंगिक बना कर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इसका प्रसार कर सकते हैं। वर्तमान में, इस तरह की प्रक्रियाओं को कुछ संगठनों द्वारा अपनाया जा रहा है तथा देश भर में वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर सक्षमता और प्रभावशीलता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रायोगिक सीएफएल परियोजना, एमईआईटीवाई का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, एनसीएफई का मनी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता के प्रसार को मजबूत करने हेतु समुदाय से हितधारकों को शामिल करने के कुछ उदाहरण हैं।

अध्याय 7: निगरानी और मूल्यांकन

7.1 यह सर्वविदित है कि किसी भी कार्यनीति का कार्यान्वयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की कार्यनीति। वित्तीय क्षेत्र में हो रहे व्यापक और तेज बदलावों को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों को वित्तीय सेवाओं के विकास की गतिशील प्रकृति और वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक सहवर्ती परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। एक मजबूत और वैज्ञानिक आंकलन प्रणाली, नीति निर्माताओं को प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनके हस्तक्षेप के प्रभाव का आंकलन करने में मदद हेतु एक लंबा रास्ता तय करेगा।

7.2 इस संबंध में कुछ व्यापक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार हैं:

- i. राष्ट्रीय कार्यनीति मूल्यांकन में कार्यान्वयन के तरीकों के अभिशासन, समन्वय और निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन, हितधारकों की भूमिका और किसी भी संचार या प्रचार योजनाओं / पहलों का प्रभाव शामिल होगा।
- ii. प्रत्येक हितधारक को कार्यनीति के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और एक स्पष्ट योजना बनाने की आवश्यकता होगी, जिसकी निगरानी गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के माध्यम से किया जा सके।
- iii. वित्तीय क्षेत्र में व्यापक बदलावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चैनलों, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के लाभार्थियों और प्रसार में शामिल मध्यस्थों दोनों से, के माध्यम से प्रतिक्रिया एकत्र करने हेतु वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए टेम्पलेट को निर्मित करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- iv. मूल्यांकन में शामिल चुनौतियों के मद्देनजर उपयुक्त मूल्यांकन पद्धतियों के चयन को अंतिम रूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

7.3 वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों के मूल्यांकन पर ओईसीडी-आईएनएफई द्वारा जारी नोट में यह सुझाया गया है कि नागरिकों की वित्तीय साक्षरता और वित्तीय व्यवहार पर प्रभाव के साक्ष्य का एक शक्तिशाली स्रोत होने के अलावा, दीर्घावधि के लिए वित्तीय शिक्षण नीतियों में सुधार करने और उनके स्थायित्व में योगदान देने के लिए मूल्यवान साक्ष्य प्रदान करने में जवाबदेही निर्धारित करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय कार्यनीति का मूल्यांकन आवश्यक है। दस्तावेज़, निगरानी (कार्यान्वयन प्रक्रिया की नियमित ट्रैकिंग की एक प्रक्रिया) और मूल्यांकन (यह समझने की एक व्यापक प्रक्रिया, कि राष्ट्रीय कार्यनीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे आगे बढ़ रही है) के बीच भी अंतर स्थापित करता है (ओईसीडी, 2019)।

निगरानी प्रणाली

7.4 वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) (अध्यक्ष: उप गवर्नर, आरबीआई), वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन और समय-समय पर उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। बुनियादी, क्षेत्र विशिष्ट और प्रक्रिया साक्षरता के प्रसार के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई गतिविधियों की आवधिक निगरानी होगी। हितधारकों द्वारा किए गए विभिन्न वित्तीय साक्षरता गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक डिजिटल रिपोर्टिंग तैयार किया जाएगा। शुरुआत में, डिजिटल रिपोर्टिंग एनसीएफई के वित्तीय साक्षरता पहलों और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से संबंधित डेटा को एकत्र करेगा, तथा बाद में विकास वित्त संस्थानों (नाबार्ड और सिडबी), वित्तीय सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों से डेटा एकत्र करेगा। प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया और विश्लेषण के आधार पर, यह डिजिटल रिपोर्टिंग उन क्षेत्रों / भू-भागों की पहचान करने में मददगार होगी जहां अधिक वित्तीय शिक्षण हस्तक्षेप की आवश्यकता है और साथ ही हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों के दोहराव को रोकने में भी मददगार सिद्ध होगी।

मूल्यांकन प्रणाली

7.5 कार्यनीति का मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो यह आंकलन करने का प्रयास करती है कि राष्ट्रीय कार्यनीति कैसे मूल्यवर्धन करेगी और क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है और निर्धारित किए गए उद्देश्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है (ओईसीडी, 2019)। उचित मूल्यांकन, कार्यनीति में किए जाने वाले वांछनीय परिवर्तन तथा अबतक जो परिवर्तन नहीं हुआ है, के संबंध में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों की निगरानी के मूल्यांकन पर ओईसीडी-आईएनएफई द्वारा जारी नोट में कार्यनीति दस्तावेज में मूल्यांकन प्रक्रिया को एकीकृत करने के महत्व तथा अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि समय क्षितिज के मूल्यांकन में समन्वयक के सक्रिय रूप से संलग्न होने को सुनिश्चित करने तथा निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के उपयोग और उसके विश्लेषण के संबंध में प्रकाश डाला गया है।

7.6 इसे ध्यान में रखते हुए, कार्यनीति के कार्यान्वयन (2022-2023) के तीन वर्ष के अंत में एक मध्यावधि मूल्यांकन संचालित किया जाएगा। कार्यनीति कार्यान्वयन की अवधि के अंत में एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में संचालित किया जाएगा।

संदर्भ

1. (2003). एडवांसिंग नेशनल स्ट्रेटिजी फॉर फ़िनान्सिअल एडुकेशन, ओईसीडी और रूस की जी20 प्रेसीडेंसी का संयुक्त प्रकाशन।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। (24 अक्टूबर 2019)। प्रगति रिपोर्ट-पीएमजेडीवाई/ प्रधानमंत्री जन धन योजना से लिया गया। <https://www.pmjdy.gov.in/account>
3. एनसीएफई-एनआईएसएम. (2013). *भारत में वित्तीय साक्षरता और समावेशन - अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013*. मुंबई: एनसीएफई-एनआईएसएम।
4. ओईसीडी. (2005). *वित्तीय साक्षरता में सुधार: मुद्दों और नीतियों का विश्लेषण*, ओईसीडी प्रकाशन.
5. ओईसीडी. (2005). वित्तीय शिक्षण और जागरूकता के लिए सिद्धांतों और अच्छी प्रथाओं की सिफारिश। पेरिस: ओईसीडी।
6. ओईसीडी. (2012). वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति पर उच्च स्तरीय सिद्धांत।
7. ओईसीडी. (2015). वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति- ओईसीडी/आईएनएफई नीति पुस्तिका। पेरिस: ओईसीडी.
8. ओईसीडी. (2016). ओईसीडी/आईएनएफई, *वयस्क वित्तीय साक्षरता सक्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण*। पेरिस: ओईसीडी.
9. ओईसीडी. (2019). वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति का मूल्यांकन। पेरिस: ओईसीडी - आईएनएफई.
10. रंगराजन, डी. सी. (2008). वित्तीय समावेशन पर समिति। मुंबई : आरबीआई.
11. विश्व बैंक समूह। (2018). *ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस*। वाशिंगटन डी सी: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक / विश्व बैंक।

अनुबंध - हितधारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल

क). एनसीएफई

एनसीएफई, सेमिनारों, वर्कशॉप, कॉन्क्ले, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, अभियानों, डिस्कसन फोरमों के जरिए खुद के द्वारा या संस्थानों, संगठनों की मदद से देश भर के लोगों के सभी वर्गों में वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण तैयार करता है तथा वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह वर्कबुक, वर्कशीट, साहित्य, पैम्फलेट्स, पुस्तिकाएं, फ्लायर, तकनीकी सहायता तैयार करता है। एनसीएफई वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल मोड पर लक्ष्य आधारित श्रोताओं के लिए उचित वित्तीय साहित्य तैयार करता है ताकि श्रोता वित्त संबंधी अपने ज्ञान, समझ, कौशल और सक्षमता में सुधार कर सकें।

बुनियादी वित्तीय शिक्षण: एनसीएफई वित्तीय शिक्षण कार्यक्रमों, जैसे एमएसएसपी (स्कूलों के लिए), स्कूल के शिक्षकों के लिए वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफईटीपी), एफएसीटी (स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए) और एफईपीए (वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम), के माध्यम से वित्तीय शिक्षण अभियान का संचालन कर रहा है।

- क). मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम (एमएसएसपी) एक शैक्षणिक वर्ष कार्यक्रम है, जहाँ स्कूल स्वैच्छिक रूप से स्कूली पाठ्यक्रम के भाग के रूप में वित्तीय शिक्षण को लागू करते हैं।
- ख). स्कूली छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता के स्तर को मापने के लिए एनसीएफई- राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षण (एनएफएलएटी), राष्ट्रीय स्तर का पहला परीक्षण है जो एनसीएफई द्वारा आयोजित किया जाता है।
- ग). एफईटीपी, स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूल शिक्षकों को निष्पक्ष व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने की एक पहल है। एनएफएलएटी की सफलता के बाद, वित्तीय शिक्षण के क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे बारी-बारी से कक्षाएं संचालित कर सकें और स्कूल के छात्रों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता कौशल प्राप्त करने में मदद कर सकें।
- घ). एफएसीटी (वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण), युवा स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों को उनके लिए आवश्यक प्रासांगिक विषयों पर वित्तीय शिक्षण, जो उनके वित्तीय खुशहाली पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम है।

ड). वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम (एफईपीए), एनसीएफई द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है। एफईपीए का उद्देश्य भारत के कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, में व्यस्कों को बुनियादी वित्तीय शिक्षण प्रदान करना है।

ख). आरबीआई

बुनियादी वित्तीय शिक्षण : आरबीआई ने बुनियादी वित्तीय शिक्षण हेतु निम्नलिखित सामग्री निर्धारित की है:

क. वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शिका, वित्तीय डायरी और आरबीआई द्वारा निर्मित 16 पोस्टरों का सेट

ख. वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए एनसीएफई द्वारा विशेष शिविरों हेतु बुकलेट तैयार किया गया है जिसमें वित्तीय खुशहाली के मूलभूत सिद्धांतों, जैसे कि बचत, उधार, ब्याज और चक्रवृद्धि की अवधारणा, मुद्रा का आवधिक मूल्य, मुद्रास्फीति, जोखिम और लाभ के बीच के संबंध, को समाहित किया गया है।

क्षेत्र केंद्रित वित्तीय शिक्षण : इस सामग्री में बैंकिंग क्षेत्र के प्रासंगिक विषय जैसे एटीएम, भुगतान प्रणाली जैसे नेफ्ट, यूपीआई, यूएसएसडी, सचेत पोर्टल के बारे में जागरूकता, पॉजी योजनाओं से दूर रहने, झूठे ई-मेल/कॉल, केवाईसी, ऋण अनुशासन अभ्यास, व्यवसाय प्रतिनिधियों, आदि, को शामिल किया गया है। आम जनता के लिए 20 संदेशों के साथ एक वित्तीय जागरूकता संदेश (एफएएमई) पुस्तिका और वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए वित्तीय साक्षरता पर पांच पोस्टरों को आरबीआई की वेबसाइट के वित्तीय शिक्षण वेबपेज पर उपलब्ध कराया गया है।

जन जागरूकता अभियान

- आरबीआई के ट्विटर हैंडल '@आरबीआई' पर महत्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनी, विवरणों, विनियामक दिशानिर्देशों, भाषणों, स्पष्टीकरणों और आयोजनों को ट्वीट किया जाता है और आरबीआई के यूट्यूब लिंक पर वीडियो प्रसारित किए जाते हैं। बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जागरूकता और समझ को विकसित करने के लिए एक अलग ट्विटर हैंडल '@आरबीआई सेज' और फेसबुक पेज 'आरबीआई सेज' पर संदेशों और हितों की जानकारी को प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक सोशल मीडिया पर लिमिटेड टू-वे संचार और सहभागिता की परिकल्पना करता है और अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति की निगरानी करता है।
- पिछले कई वर्षों से, आरबीआई लगातार आउटरीच कार्यक्रमों, वित्तीय साक्षरता पहल, जन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में उपस्थिति, आदि, के माध्यमों से आम जनता तक पहुँच रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक, 'जन जागरूकता अभियान', जिसका उद्देश्य बैंकिंग से संबंधित मामलों में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में आम जनता को शिक्षित करना है, के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों

से अपेक्षित सुविधाओं और सेवाओं के बारे में आम जनता को सूचित करके उन्हें सशक्त बना रहा है। यह अभियान नियमित रूप से 'आरबीआई कहता है' टैगलाइन के तहत समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, सिनेमा, डिजिटल चैनलों, एसएमएस और होर्डिंग्स के माध्यम से पूरा किया जाता है।

- वीडियो संदेशों के लिए, वर्तमान में, कुछ क्रिकेटर्स और बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी हैं और आईपीएल / पीबीएल की विभिन्न टीमों का हिस्सा हैं, का सहयोग लिया जा रहा है। इन वीडियो के संदेश कई स्तरों पर कार्य करते हैं। मुख्य संदेश के अलावा, वीडियो की कहानी दर्शकों के साथ तत्काल एक भावनात्मक जुड़ाव भी बनाती है और संवादात्मक पटकथा बैंक खाते से संबंधित दुरुह बातों जैसे शुष्क विषय में मानव दिलचस्पी को जीवंत बनाए रखने में मदद करती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का जन जागरूकता अभियान 2017 में शुरू हुआ और 2018 में इसमें गति आनी शुरू हुई। सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, सीमित देयता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग में आसानी जैसे विज्ञापन लोकप्रिय कार्यक्रमों जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), 2018 फीफा विश्व कप, एशियन गेम्स, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), प्रो कबड्डी लीग, प्रो बैडमिंटन लीग और भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दिखाये गए हैं।
- बीएसबीडीए पर बनी एक फिल्म यह बताती है कि इस प्रकार के खाते खोलने से कैसे इसमें न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता कम हो जाती है। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर बनी एक फिल्म डिजिटल लेनदेन करते समय कार्ड और पिन विवरण साझा करने के बारे में जनता को सावधान करती है। सीमित देयता पर बनी एक अन्य फिल्म कार्ड धोखाधड़ी की स्थिति में उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताती है। 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग में आसानी' पर बनी एक फिल्म में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध डोरस्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाओं के बारे में बताया गया है। क्रिकेटर्स और बैडमिंटन खिलाड़ियों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी हैं, का उपयोग करके बनाई गई इन फिल्मों को मीडिया विज्ञापनों में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।
- जन जागरूकता अभियान की एक अनूठी विशेषता मिस्ड कॉल सुविधा है: 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल देने पर, कॉल करने वाले को पहले से रिकॉर्ड किए गए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि एक कॉल सेंटर दृष्टिकोण के तहत गलत सूचना या अनावश्यक सूचना से बचाता है। गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मोबाइल फोन ग्राहकों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में संदेश मिलते हैं, ताकि आम जनता के साथ तत्काल जुड़ाव हो सके और सभी को इसमें शामिल किया जा सके।

ग. सेबी

बुनियादी वित्तीय शिक्षण : सेबी ने बुनियादी वित्तीय शिक्षण हेतु निम्नलिखित पहल की है:

क. आम जन को वित्तीय शिक्षण प्रदान करने के लिए रिसोर्स पर्सन कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय शिक्षण। सेबी द्वारा पात्र व्यक्तियों, जो स्थानीय भाषा में मुफ्त कार्यशालाएं आयोजित कर सकें, को प्रशिक्षित कर उन्हें आरपी (जिलों में) के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है तथा उन्हें कार्यशाला आयोजित करने पर मानदेय का भुगतान भी किया जाता है। वित्त, बैंकिंग, बीमा, पेंशन और निवेश की बुनियादी अवधारणाओं को पांच लक्षित समूहों (अर्थात् होम मेकर्स, स्वयं सहायता समूह, एकजीक्यूटिव, मध्य आय समूह, सेवानिवृत्त कर्मी) के लिए निर्मित सामग्री में शामिल किया गया है। कार्यशालाओं के दौरान, निःशुल्क वित्तीय शिक्षण पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं।

ख. छात्रों द्वारा सेबी का दौरा

ग. वित्तीय शिक्षण पुस्तिका में वित्तीय योजना, बचत, निवेश, बीमा, पेंशन, उधार, कर बचत, पॉजी योजनाओं के प्रति सावधानी, शिकायत निवारण आदि, जैसी अवधारणाओं की मूल बातें को समाहित किया गया है।

क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय शिक्षण: सेबी ने क्षेत्र केंद्रित वित्तीय शिक्षण के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

क. सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त निवेशक संघों द्वारा निवेशक जागरूकता कार्यक्रम

ख. एक्सचेंज / डिपॉजिटरी के सहयोग से क्षेत्रीय सेमिनार

ग. सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रशिक्षकों द्वारा कमोडिटी जागरूकता कार्यक्रम
उपरोक्त के अलावा, सेबी ने निम्नलिखित पहलें भी की हैं:

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के सहयोग से विश्व निवेशक सप्ताह में भागीदारी:** निवेशक संरक्षण और शिक्षण जागरूकता गतिविधियों के संचालन की दिशा में विभिन्न वित्तीय बाजार विनियामकों द्वारा की गई पहलों को उजागर करने के उद्देश्य से, आईओएससीओ प्रति वर्ष एक सप्ताह की अवधि के लिए वैश्विक अभियान आयोजित करता है जिसे विश्व निवेशक सप्ताह (डब्लूआईडब्लू) कहा जाता है। सेबी ने देशभर में इस सप्ताह के दौरान विभिन्न वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुये आईओएससीओ डब्लूआईडब्लू में सहभागिता की।
- **समर्पित निवेशक वेबसाइट:** निवेशकों के लाभ के लिए एक समर्पित वेबसाइट <http://investor.sebi.gov.in> का रखरखाव किया जाता है। यह वेबसाइट प्रासंगिक शैक्षिक / जागरूकता सामग्री और अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, निवेशकों की जानकारी के लिए विभिन्न निवेशक और वित्तीय शिक्षण कार्यक्रमों की सूची भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

- **जन मीडिया अभियान:** लोगों तक पहुंचने के लिए, सेबी ने लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से निवेशकों को प्रासंगिक संदेश देते हुए एक जन मीडिया अभियान की शुरुआत की है। वर्ष 2012 से, सेबी ने निम्नलिखित विषयों पर मल्टी मास मीडिया (टीवी / रेडियो / प्रिंट / बल्क एसएमएस) में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए हैं:
 - निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली
 - सामूहिक निवेश योजना - अवास्तविक प्रतिलाभ।
 - सामूहिक निवेश योजना - अफवाहों के झांसे में न आना।
 - अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)।
 - डबबा ट्रेडिंग
 - हॉट टिप्स के प्रति सावधानी

इसके अतिरिक्त, ऊपर सूचीबद्ध सावधानी संदेशों पर बनाए पोस्टरों को विभिन्न भाषाओं में मुद्रित किया गया था और विभिन्न भाषाओं में जिला कलेक्टरों, पंचायत कार्यालयों आदि, को वितरित किए गए थे।
- **निवेशक शिकायत निवारण:** सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के लिए कई विनियामक उपाय किए हैं। निवेशकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित सूचीबद्ध कंपनी या मध्यस्थ के समक्ष उठाया जाता है और उसपर निरंतर निगरानी की जाती है। सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरईएस) निवेशकों को उनकी शिकायतों की स्थिति हेतु वास्तविक समय में जानकारी देते हैं क्योंकि निवेशक किसी भी समय और कहीं से भी शिकायत दर्ज करने के समय उन्हें प्रदान किए गए यूजर-नेम और पासवर्ड की मदद से एससीओआरईएस पर लॉग इन कर सकते हैं और अपने शिकायतों की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- **सेबी टोल फ्री हेल्पलाइन:** सेबी ने 30 दिसंबर 2011 को एक टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा संख्या 1800 22 7575/1800 266 7575 की शुरुआत की थी। यह हेल्पलाइन सेवा प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (महाराष्ट्र में घोषित सार्वजनिक अवकाश के अलावा) पूरे भारत के निवेशकों के लिए उपलब्ध है। यह हेल्पलाइन सेवा अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

घ. आईआरडीएआई

अपनी स्थापना के बाद से ही, आईआरडीएआई ने वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में कई पहल की हैं। टेलीविजन और रेडियो पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और पॉलिसीधारकों के अधिकारों और कर्तव्यों, विवाद निवारण के लिए उपलब्ध चैनलों आदि के बारे में सरल संदेश को निरंतर अभियानों के द्वारा टेलीविजन और रेडियो के साथ-साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया गया है।

आईआरडीएआई ने बीमा जागरूकता सृजित करने की अपनी कार्यनीति में सुधार के लिए एनसीईआर के माध्यम से बीमा के बारे में जागरूकता स्तर पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण संचालित किया है। आईआरडीएआई ने बीमा पहुँच और जागरूकता बढ़ाने के अपने अभियानों की प्रभावशीलता को मापने के लिए एक पोस्ट लॉन्च सर्वेक्षण का आयोजन भी किया था। आईआरडीएआई ने 'पॉलिसीहोल्डर हैंडबुक' के प्रकाशनों के साथ-साथ बीमा पर एक कॉमिक बुक श्रृंखला भी प्रकाशित की है। पॉलिसीधारकों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए बीमा पर उपभोक्ता शिक्षण हेतु एक समर्पित वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। आईआरडीएआई का एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) देश भर में शिकायतों का एक केंद्रीय रिपोर्टिंग सृजित करता है और बीमा पॉलिसीधारक के लिए चिंताजनक क्षेत्रों के डेटा सूचक का विभिन्न विश्लेषण उपलब्ध करता है।

आईआरडीएआई द्वारा संचालित की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:

- सेमिनार, जागरूकता अभियान, मेट्रो रेल अभियान, क्विज़, आदि का आयोजन।
- पॉलिसीधारकों की वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव सिक्स गेम फीचर 'यंग कर्नर' लॉन्च किया गया था। वेबसाइट की पहुंच को बढ़ाने के लिए उसके हिंदी संस्करण को भी लॉन्च किया गया था।
- आम जनता को जाली कॉलर्स और संदेहास्पद प्रस्तावों के बारे में सतर्क करते हुए प्रिंट अभियान चलाया गया। 12 स्थानीय भाषाओं में बीमा कॉमिक पुस्तकें जारी की गईं।
- बीमा पर पुस्तिकाएँ, जैसे छात्रों के लिए बीमा में रोजगार के अवसर, फसल बीमा, सही खरीद आदि, जारी की गई थी।
- पांच क्षेत्रीय भाषाओं में बीमा के विभिन्न रूपों की उपयोगिता और लाभों पर टीवी विज्ञापनों और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से जाली कॉलर्स के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया गया।

इ. पीएफआरडीए

पीएफआरडीए ने 2018 में एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम “पेंशन संचय” है। इस वेबसाइट के माध्यम से, पीएफआरडीए का उद्देश्य सेवानिवृत्ति योजना के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता को संबोधित करना है। वेबसाइट की सामग्री को वित्तीय निर्णय लेने में चार सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं, अर्थात् ब्याज दरों, चक्रवृद्धि ब्याज, मुद्रास्फीति और जोखिम विविधीकरण का ज्ञान, को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। वेबसाइट में अलग से एक ब्लॉग सेगमेंट है, जहां वित्तीय क्षेत्रों के पेशेवरों और प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लिखे गए ब्लॉग को उपलब्ध कराया जाता है, जो वित्त, बैंकिंग और निवेश की बुनियादी बातों के बारे में सार्थक जानकारी प्रदान करता है।

पीएफआरडीए पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने केंद्रीय रिकॉर्ड किपिंग एजेंसियों के माध्यम से ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, पीएफआरडीए ने एनपीएस और एपीवाई के बारे में ग्राहकों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण एजेंसी को भी सूचीबद्ध किया है। उपरोक्त के अलावा, पीएफआरडीए, एनपीएस ट्रस्ट और एन्युइटी सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके एन्युइटी साक्षरता कार्यक्रम का भी आयोजन करता है, जो ग्राहकों को उनके लिए उपलब्ध विभिन्न एन्युइटी के बारे में जागरूक करता है।

च. नाबार्ड

- ग्रामीण जनता के बीच हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में विभिन्न माध्यमों से वित्तीय जागरूकता सृजित करना। (वित्तीय साक्षरता पहल पर सामग्री, जैसे लिफलेट, पोस्टर, किताबें / पुस्तिकाएं, मुद्रित की गई; वित्तीय समावेशन से संबंधित जिंगल, जैसे बैंक खाते खोलना, एसचजी बचत, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, आदि का प्रसारण किया गया, और ऋण, बजट एवं एटीएम के उपयोग पर आधारित एनिमेटेड फिल्मों को नाबार्ड की वेबसाइट के साथ-साथ यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया)
- डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों पर ग्रामीण जनता के लिए वित्तीय शिक्षण के अलावा वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगो, व्यस्कों, किसानों, स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को लक्ष्य करके वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी) संचालित किया जाता है।
- डिजिटल लेनदेनों के संचालन के लिए हैंडहोल्डिंग तथा माइक्रो-एटीएम, एटीएम, ऑडियो-वीडियो उपकरण से लैस मोबाइल डेमो वैन के साथ एफएलएपी का संचालन (नया बिंदु)

- बीआईआरडी के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के प्रभावी वितरण के लिए वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और आरसीबी के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण पहल, तथा एटीएम और / या माइक्रो-एटीएम से लैस मोबाइल प्रदर्शन वैन की तैनाती के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना
- आजीविका प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण उपकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) / ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआई) को समर्थन प्रदान करना।
- वित्तीय साक्षरता के प्रभावी वितरण के लिए वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और आरसीबी के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने हेतु क्षमता निर्माण पहल।
- बैंकों के बीसी / बीएफ के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

नाबार्ड ने बैंकों (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरसीबी, आरआरबी) को सूचित किया है कि वे उनकी शाखाओं और एफएलसी द्वारा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों के लिए एफआईएफ से सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यवार तिमाही योजना का निर्माण करें। इन योजनाओं में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और एफआई पर एसएलबीसी उप समिति में की गई चर्चा, बैंकों के एफआईपी पर आधारित क्षेत्रों, अपवर्जित ब्लॉकों पर विशेष ध्यान देने के साथ लक्ष्य समूह अर्थात एसएचजी, छात्रों, वरिष्ठ नागरिक; किसानों; छोटे उद्यमियों आदि, को शामिल किया जाए। एफआईएफ से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए बैंकों के साथ नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय तिमाही आधार पर समीक्षा करता है और एसएलबीसी की एफआई उप समिति में भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

छ. सिडबी

- समृद्धि, एक वर्चुअल सहायक जिसे 02 अप्रैल 2018 को उदमी मित्र पोर्टल पर सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वर्चुअल सहायक, ऋणों के प्रकार से लेकर हैंडहोल्डिंग सहायता तक के विषयों के एक विस्तृत भाग के बारे में उभरते हुए उद्यमी को मार्गदर्शित करता है। (अंग्रेजी और हिंदी में संचालित)
- द्विभाषी प्रारूप में "एमएसई उद्यमियों के लिए एक बैंकेबिलिटी किट" को पोर्टल पर होस्ट किया गया है। यह उद्यमियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घटकों के अलावा स्वयं का आंकलन करने, बैंक क्या चाहते हैं इसपर अवलोकन करने, बैंकों के साथ संवाद स्थापित करने हेतु टिप्स, एमएसएमई के लिए वित्तीय उत्पादों, के संबंध में वन स्टॉप गाइड है।

- प्रमाणित क्रेडिट काउंसलरों और सीसीआई को सूचीबद्ध किया गया है एवं उसे उद्यमी मित्र प्लेटफॉर्म पर रखा गया है, जिससे एमएसएमई पक्ष के मांग मुद्दों, विशेष रूप से पिरामिड के निचले भाग में, को बढ़ाने में गति मिल सके तथा साथ ही क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाकर आपूर्ति पक्ष को भी मजबूत किया जा सके।
- उद्यमी मित्र पोर्टल का लक्ष्य एमएसएमई की वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा आवश्यकताओं तक पहुंच को आसान बनाना है। यह पोर्टल संदर्भ उद्देश्य के लिए 40 औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करते हुए 325 परियोजना से संबंधित प्रोफाइल को भी पेश करता है। 7618 से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों ने 50680 जानकारी और आकांक्षी उद्यमियों की अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों में सहायता की है। प्रमाणित क्रेडिट काउंसलर भी उद्यमियों को उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं तथा उन्हें उधारदाताओं से उचित रूप से जोड़ रहे हैं।
- सिडबी ने राष्ट्रव्यापी कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के समर्थन के साथ एक उद्यमिता जागरूकता अभियान या उद्यमअभिलाषा परियोजना की शुरुआत की है जो 28 राज्यों में 115 आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन 115 जिलों में देश की 20% से अधिक आबादी रहती है और इसमें 8,600 से अधिक ग्राम पंचायत हैं। अभियान के दौरान 18000+ युवाओं (लगभग 35% महिलाओं सहित) को प्रदान किए गए 2.25 लाख घंटे के इनपुट के साथ लगभग 470 प्रशिक्षण स्थानों को कवर किया गया था।
- सिडबी ने जनता के बीच सूचना के प्रसार के लिए हौजखास मेट्रो स्टेशन (नई दिल्ली में) को एक थीम आधारित स्टेशन के रूप में अपनाया है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सीजीटीएमएसई, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सिडबी की पेशकशों, भारत सरकार की पहलों आदि, से जोड़ना है।
- हाल ही में आयोजित कुंभ मेले के दौरान, सिडबी ने एक स्वावलंबन स्टाल स्थापित करके एक विशेष परियोजना की शुरुआत की और खेल (कौन बनेगा उद्यमी), नुक्कड़ नाटक / कठपुतली प्रदर्शन, वित्तीय साक्षरता वीडियो और विभिन्न योजनाओं जैसे कि मुद्रा, सीजीटीएमएसई, स्टैंडअप इंडिया, आदि, के प्रसार द्वारा जानकारी दिये जाने के माध्यम से देशभर में उद्यमशीलता संस्कृति को फैलाने के उद्देश्य से वित्तीय जागरूकता सृजित करने का प्रयास किया।

ज. एनपीसीआई

- एनपीसीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ रुपये, आईएमपीएस, ईपीएस और यूएसएसडी -* 99 # पर जागरूकता फैलाने और साक्षरता सत्रों को संचालित करने पर कार्य आरंभ कर दिया है। एनपीसीआई सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ संबद्ध था। जागरूकता और

साक्षरता सत्रों का संचालन करते हुए एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान साक्षरता और धोखाधड़ी जागरूकता पर पोस्टरों, एटीएम स्क्रीन, वेब बैनरों, एसएमएस, ईमेल आदि को भी वितरित किया।

- इन एजेंसियों की मदद से, कॉर्पोरेट कर्मचारियों और लाभार्थियों में डिजिटल भुगतान साक्षरता का प्रसार किया गया। वर्तमान में, डिजिटल भुगतान साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये बैंकों के अलावा भारतीय रेलवे, ओएमसी, नाबार्ड, शिक्षा संस्थान, कॉर्पोरेट सीएसआर, एनयूएलएम, एमएफआई, बीसी, एनजीओ, एग्रीटेक, फिनटेक आदि, के साथ संबद्ध हैं।
- विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर दिनांक 8 सितंबर 2015 को देश भर में एक साथ 120 ई-पेमेंट साक्षरता शिविरों को आयोजित करने के लिए इसे वर्ष 2017 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। कार्यशाला में 23,930 ग्राहक शामिल हुए थे।

NATIONAL STRATEGY FOR FINANCIAL EDUCATION 2020 - 2025

Creating a Financially Aware and Empowered India



NATIONAL STRATEGY FOR FINANCIAL EDUCATION 2020 - 2025

*A Multi-Stakeholder led approach for creating
a Financially Aware and Empowered India*

Contents

List of Select Abbreviations.....	i
Executive Summary	1
Chapter 1: Introduction.....	4
Chapter 2: Overview of Progress under 1 st NSFE (2013-2018)	8
Chapter 3: Assessment of the Needs and Critical Gaps	10
Chapter 4: Vision and Strategic Objectives of NSFE (2020-2025).....	17
Chapter 5: Policy Design.....	20
Chapter 6: Action Plan to Achieve the Strategic Objectives	22
Chapter 7: Monitoring and Evaluation.....	32
References	34
Annex - Financial Literacy Initiatives by Stakeholders.....	35

List of Figures, Charts and Box Items

Figure 1: Vision & Strategic Objectives of NSFE (2020-2025)	19
Figure 2: Institutional Arrangement Flow Chart and Responsibilities of each Stakeholder	29
Chart 1: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Gender-wise.....	11
Chart 2: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Zone-Wise.....	11
Chart 3: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Occupation-wise	12
Chart 4: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Annual Income-wise.....	12
Chart 5: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Rural-Urban	13
Chart 6: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Education-wise.....	13
Chart 7: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Social Category-Wise	14
Chart 8: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score Age Wise (2019)	14
Box Item 1: Learning by Doing.....	9
Box Item 2: OECD-INFE Definition of Components of Financial Literacy	10
Box Item 3: Technology and Civil Society for Improving Financial Literacy	31

List of Select Abbreviations

AMFI	Association of Mutual Funds in India
APY	Atal Pension Yojana
ATM	Automated Teller Machine
BC	Business Correspondent
BCFI	Business Correspondent Federation of India
B.Ed.	Bachelor of Education
BIRD	Bankers Institute of Rural Development
BSBDA	Basic Savings Bank Deposit Account
CGTMSE	Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
CISCE	Council for the Indian School Certificate Examinations
CFL	Centre for Financial Literacy
CSC	Common Service Centres
CSR	Corporate Social Responsibility
FACT	Financial Awareness and Consumer Training
FEDAI	Foreign Exchange Dealers Association of India
FEPA	Financial Education Program for Adults
FETP	Financial Education Training Programme
FIDC	Finance Industry Development Council
FLC	Financial Literacy Centre
FSDC	Financial Stability and Development Council
FSDC-SC	Financial Stability and Development Council- Sub Committee
GPFI	Global Partnership for Financial Inclusion
IBA	Indian Banks' Association
IEPFA	Investor Education and Protection Fund Authority
IICA	Indian Institute of Corporate Affairs
INFE	International Network on Financial Education
IOSCO	International Organization of Securities Commissions
IPPB	India Post Payments Bank
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
LWE	Left Wing Extremism
MCA	Ministry of Corporate Affairs
M.Ed.	Master of Education
MW&CD	Ministry of Women and Child Development
MeitY	Ministry of Electronics and Information Technology
MoF	Ministry of Finance
MoRD	Ministry of Rural Development
MH&FW	Ministry of Health and Family Welfare
MHRD	Ministry of Human Resource Development
MI&B	Ministry of Information and Broadcasting
MSD&E	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
MSE	Micro and Small Enterprise
MSJ&E	Ministry of Social Justice and Empowerment
MSME	Micro Small and Medium Enterprise
MUPA&HA	Ministry of Urban Poverty Alleviation and Housing Affairs

NCAER	National Council of Applied Economic Research
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NCFE	National Centre for Financial Education
NPCI	National Payments Corporation of India
NPS	National Pension System
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NER	North East Region
NFLAT	National Financial Literacy Assessment Test
NRLM	National Rural Livelihood Mission
NSFE	National Strategy for Financial Education
NULM	National Urban Livelihood Mission
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PFRDA	Pension Fund Regulatory Authority of India
PMJDY	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
PMMY	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMJJBY	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
PMSBY	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-KMY	Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana
PM-SYM	Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana
RBI	Reserve Bank of India
RSETI	Rural Self Employment Training Institute
RUDSETI	Rural Development & Self Employment Training Institute
SDG	Sustainable Development Goals
SEBI	Securities Exchange Board of India
SIDBI	Small Industries Development Bank of India
SRLM	State Rural Livelihood Mission
TGFIFL	Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy
UGC	University Grants Commission
UPI	Unified Payments Interface

Executive Summary

Strengthening Financial Inclusion in the country has been one of the important developmental agendas of both the Government of India and the four Financial Sector Regulators (viz. RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA). Financial literacy supports the pursuit of financial inclusion by empowering the customers to make informed choices leading to their financial well-being.

2. Subsequent to completion of the period of the first National Strategy for Financial Education (NSFE: 2013-2018), a review of the progress made was undertaken by the Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL- Chair: Deputy Governor, RBI) under the Financial Stability and Development Council (FSDC-Chair: Hon'ble Union Finance Minister). Based on the review of progress made under the Strategy and keeping in view the various developments that have taken place over the last 5 years¹, notably the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)², the National Centre for Financial Education (NCFE) in consultation with the four Financial Sector Regulators and other relevant stakeholders has prepared the revised NSFE (2020-2025).

3. The NSFE document intends to support the Vision of the Government of India and Financial Sector Regulators by empowering various sections of the population to develop adequate knowledge, skills, attitude and behaviour which are needed to manage their money better and plan for their future. The Strategy recommends adoption of a Multi-Stakeholder Approach to achieve financial well-being of all Indians.

4. To achieve the vision of creating a financially aware and empowered India, the following Strategic Objectives have been laid down:

- i. Inculcate financial literacy concepts among the various sections of the population through financial education to make it an important life skill
- ii. Encourage active savings behaviour
- iii. Encourage participation in financial markets to meet financial goals and objectives
- iv. Develop credit discipline and encourage availing credit from formal financial institutions as per requirement
- v. Improve usage of digital financial services in a safe and secure manner
- vi. Manage risk at various life stages through relevant and suitable insurance cover
- vii. Plan for old age and retirement through coverage of suitable pension products

¹ Increased penetration of mobile phones, retail digital transactions, growing adult population in the country, entry of Payments and Small Finance Banks, Fin-Tech players and awareness on the need to manage one's finances.

² PMJDY also known as the National Mission for Financial Inclusion, was launched by Hon'ble Prime Minister of India in August 2014. For further details please see explanation for Foot note No. 3 in page 6 (Chapter -01).

- viii. Knowledge about rights, duties and avenues for grievance redressal
- ix. Improve research and evaluation methods to assess progress in financial education

5. In order to achieve the Strategic Objectives laid down, the document recommends adoption of a **‘5 C’ approach** for dissemination of financial education through emphasis on development of relevant **Content** (*including Curriculum in schools, colleges and training establishments*), developing **Capacity** among the intermediaries involved in providing financial services, leveraging on the positive effect of **Community** led model for financial literacy through appropriate **Communication** Strategy, and lastly, enhancing **Collaboration** among various stakeholders.

6. The recommendations laid down in the Strategy under each of the **‘5 Cs’** are as under:

Content

- Financial Literacy content for school children (including curriculum and co-scholastic), teachers, young adults, women, new entrants at workplace/ entrepreneurs (MSMEs), senior citizens, persons with disabilities, illiterate people, etc.

Capacity

- Develop the capacity of various intermediaries who can be involved in providing financial literacy.
- Develop a ‘Code of Conduct’ for financial education providers.

Community

- Evolve community led approaches for disseminating financial literacy in a sustainable manner.

Communication

- Use technology, mass media channels and innovative ways of communication for dissemination of financial education messages.
- Identify a specific period in the year to disseminate financial literacy messages on a large/ focused scale.
- Leverage on Public Places with greater visibility (e.g. Bus Stands, Railway Stations, etc.) for meaningful dissemination of financial literacy messages.

Collaboration

- Preparation of an Information Dashboard.

- Integrate financial education content in school curriculum, various Professional and Vocational courses (undertaken by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSD&E) through their Sector Skilling Missions and the likes of B.Ed./M.Ed. programmes.
- Integrate financial education dissemination as part of various on-going programmes.
- Streamline efforts of other stakeholders for financial literacy.

The Strategy also suggests adoption of a robust 'Monitoring and Evaluation Framework' to assess the progress made under the Strategy.

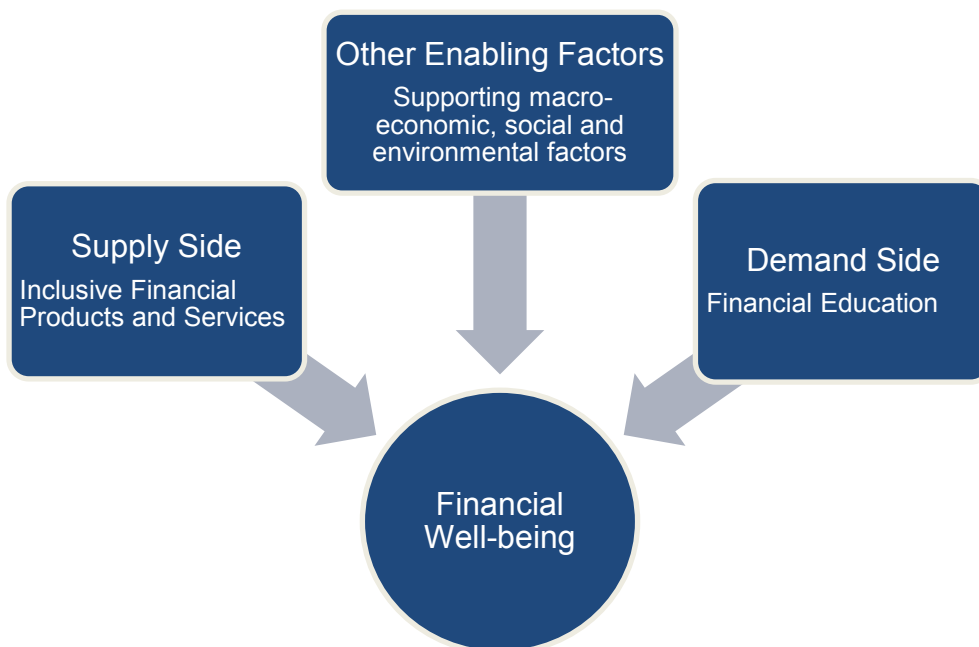
Chapter 1: Introduction

1.1 The Organization for Economic Co-operation & Development (OECD) defines Financial Literacy and Financial Education. **Financial Literacy** is defined as a combination of financial awareness, knowledge, skills, attitude and behaviour necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial well-being (OECD, 2012). **Financial Education**, on the other hand is defined as the process by which financial consumers/investors improve their understanding of financial products, concepts and risks and through information, instruction and/or objective advice, develop the skills and confidence to become more aware of financial risks and opportunities, to make informed choices, to know where to go for help and to take other effective actions to improve their financial well-being” (OECD, 2005).

1.2 As can be seen, the term Financial Education and Financial Literacy are not the same, these are related concepts. People achieve Financial Literacy through the process of Financial Education. The achievement of Financial Literacy empowers the users to make sound financial decisions which result in financial well-being of the individual.



1.3 The financial service sector in India has undergone significant changes in the last 5 years and the sector has been ever widening. There is a need to increase the size of banking as well as other financial sectors to ensure that the benefits of these developments reach the common masses. Financial inclusion is a National priority of Government of India and the Financial Sector Regulators (RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA) as it is an enabler for inclusive growth. In the Indian context, financial inclusion is the process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institutional players. Financial inclusion provides an avenue to the poor for integrating with the formal financial system. While financial inclusion is essentially a supply-side intervention, financial education is a demand side intervention. Apart from these forces operating on the demand side and supply side, there are also other enabling factors on the ground. Achievement of financial well-being of citizens of any country depends on how well these factors and forces are integrated and the extent to which these work in cohesion.



1.4 Financial education plays a vital role in creating demand side response to the initiatives of the supply side interventions. Financial education initiatives by concerned stakeholders will help people achieve financial well-being by accessing appropriate financial products and services through regulated entities. These efforts will be guided by the National Strategy for Financial Education (NSFE). Incidentally, financial education also supports achievement of Sustainable Development Goal (SDG) No. 4 on Education which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all (SDG Target 4.6 on Literacy and SDG Target 4.4 on Life Skills under SDG 4 on Education).

1.5 India has made tremendous progress in bringing its citizens into the formal financial system over the last many years. Since India's first NSFE was released in 2013, there have been many developments in the financial inclusion scenario of the country. During this period, important financial inclusion initiatives by Government of India such as Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY), social security schemes viz. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Atal Pension Yojana (APY), Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY), Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana (PM-SYM) and Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) have changed the financial inclusion landscape. These initiatives are not only bringing the excluded sections into the financial mainstream but also ensuring access to various financial services such as Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA), need based credit, remittance facility, insurance and pension to the excluded sections.

1.6 The latest available World Bank's Findex 2017 Report had brought out that the proportion of adults with a formal account in the country has risen from 35% in 2011, to 53% in 2014, to 80% in 2017. India has also made extraordinary progress in reducing the country's gender gap in account ownership, from nearly 20% in 2014 to 6% in 2017 (World Bank Group, 2018). Much of this improvement can be attributed to the flagship initiative of the Government of India towards financial inclusion, namely the PMJDY³, supported by the conducive ecosystem created by the financial sector regulators. In order to take forward the benefits achieved through the financial inclusion efforts, financial literacy will have to play a central role in ensuring that people use appropriate formal financial services to ensure their financial well-being (Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, 2019).

Background and Rationale of NSFE

1.7 India has a large population of adults⁴. This demographic advantage can be leveraged to ensure that India becomes one of the fastest growing economies, with emphasis on inclusive growth through a vibrant and stable financial system. Since a large number of stakeholders, including the Central and State governments, Financial Sector Regulators, financial institutions, civil society, academia, educational institutions in public and private sector and others are involved in spreading financial literacy, a broad National Strategy for Financial Education (NSFE) is a pre-requisite to ensure that they work in tandem and their work is aligned to the overall Strategy on financial education and not at cross purposes. In recent years, it is increasingly being recognized that Nation-wide financial literacy can be achieved only through a multi-stakeholder approach wherein different stakeholders viz. Government, Financial Sector Regulators, Financial Service providers, civil society, academia (both in public and private sector), etc. have a role to play.

³ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) launched in August 2014 is a National Mission on Financial Inclusion encompassing an integrated approach to bring about comprehensive financial inclusion of all the households in the country. The plan envisaged universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension facility. The plan also envisages channelling all Government benefits (from Centre / State / Local Body) to the beneficiaries' accounts and pushing the Direct Benefits Transfer (DBT) scheme of the Union Government. Subsequently, the Government decided to continue National Mission for Financial Inclusion (PMJDY) beyond August 2018 with focus of opening account from every household to every adult. So far 37.70 Crore bank account have been opened under PMJDY (as on December 18, 2019). For more details see <http://www.pmjdy.gov.in/>

⁴ The population of India is 1,370,862,591 as of October 29, 2019, based on Worldometers elaboration of the latest United Nations data. The age group (15-64) constitutes 67.27% of the total population and the median age is 27.1 (<https://www.worldometers.info/world-population/india-population/>)

1.8 National Strategy for Financial Education is defined as “a nationally co-ordinated approach to financial education that consists of an adapted framework or programme” (OECD, 2019). The NSFE document intends to support the vision of the Government of India and Financial Sector Regulators by enabling various sections of the population to develop knowledge, skills, attitude and behaviour which are needed to manage their money better and to plan for their future. The document also takes stock of the current work done by various stakeholders and adopts a multi-stakeholder approach to achieve financial well-being of Indians.

1.9 Towards this objective, the National Centre for Financial Education (NCFE) has been set up by all the Financial Sector Regulators as a Section (8) company under Companies Act, 2013 to undertake basic financial education and to develop suitable content for increasing financial literacy among the masses in the country.

1.10 Over the last few years, there has been rapid progress towards digitalization which has brought newer opportunities to the forefront like never before. This Digital revolution has been supported by initiatives like Digital India Campaign, Digital Saksharta Abhiyan, etc. There is a paradigm shift in digital transactions and Payment Infrastructure in the country (Goal of Less Cash Economy). Due to all these developments, it has become imperative to revise the existing National Strategy for Financial Education (NSFE) and to adopt innovative measures to implement the same. The National Strategy for Financial Education (2020-2025) inter-alia focuses on advancement of skills of financial service providers and other intermediaries involved in dissemination of financial literacy.

1.11 It is envisaged that implementing the Strategy would go a long way in furthering financial literacy across the country and result in positive behavioural outcomes among the population emanating from the Strategic Objectives laid down in the document.

Chapter 2: Overview of Progress under 1st NSFE (2013-2018)

2.1 Since the launch of the first National Strategy for Financial Education (NSFE) in 2013, different stakeholders have undertaken several measures to improve financial literacy of the cross-section of population in the country. A snapshot of the initiatives undertaken by the various stakeholders is summarized in Annex. The key learnings from the programmes of financial literacy implemented during the 1st NSFE (2013-2018) are summarized below:

- i. **Target Specific Modules:** A one size fits all approach for delivering financial literacy results in sub-optimal outcomes. Target specific modules need to be developed for effective dissemination of financial literacy messages.
- ii. **Contextual & Vernacular Approach:** The language and mode of delivery of financial literacy messages should be appealing to the target audience in an easy to understand manner. For example, Nukkad Natak (Street plays in local languages) was found to be an effective tool for delivering financial literacy.
- iii. **Medium and Mode of Delivery:** Multi-media modes like Audio-Visuals, Digital Vans (Digital financial literacy on wheels), Digital Display Systems, Kiosks, etc. have been found to be best tools for promoting digital financial literacy. Regarding mode of delivery, one-to-one learning and group trainings were found to be effective modes of dissemination of financial literacy messages.
- iv. **Learning While Doing & Peer-to-Peer Learning:** Learning is long lasting when accompanied by a hands-on effort/ demonstration besides repetitive relaying of messages. For example, practical training on usage of digital financial transaction using mobile vans (Digital Vans) etc.
- v. **Efficacy in Mass Media Outreach:** Among mass media campaigns, messages broadcast through television had the highest recall among the audience as compared to other modes of broadcasting.
- vi. **Rationalising Stakeholder Collaborations:** Collaboration among all the stakeholders of financial education is important. For example, RBI is piloting the concept of Centre for Financial Literacy (CFL) which aims to leverage the strengths of banks and NGOs to explore innovative channels for delivery of financial literacy. Similarly, SEBI is undertaking investor education program in collaboration with Stock Exchanges and Depositories for delivery of financial literacy.
- vii. **Use of Relatable Examples:** Financial literacy messages when co-related with real life events (e.g. marriage, parenting, retirement planning, asset acquisition) seem to have higher connect to various target audiences.
- viii. **Creating Positive Behavioral Outcomes:** More efforts are needed to understand how financial education programmes can be curated to translate into positive behavioral outcomes.

- ix. **Expanding the Digital Base:** Given the rapid pace of progress made in digital financial services, focused efforts are needed to strengthen knowledge on safe digital financial practices.

The key learnings, as detailed above, have been incorporated in the Strategic Objectives (Chapter 4), Policy Design (Chapter 5), and Action Plan (Chapter 6).

Box Item 1: Learning by Doing

I hear and I forget; I see and I remember; I do and I understand.

The above quote is relevant in the context of learning. It is well known that the goal of any financial education intervention is to result in financial well-being through desirable financial behaviour among the target audience. In the past, lot of efforts in financial literacy campaigns focused on developing content, improving knowledge and attitude of the participants. Over the years, there have been significant developments in improving financial literacy through demonstration and practical sessions in the form of kiosks and other sources. Among various initiatives that have been taken to improve financial literacy, street plays, dramatics and demonstration methods have been found to have higher appeal among the target audience. For example, Mobile Demo Vans fitted with ATM, Micro-ATM, SEBI's Resource Persons and Financial Literacy Centre (FLC) Counsellors of banks are enabling people in remote villages to conduct digital transactions for the first time, under guidance. This method of learning by doing digital transactions is taking away the fear from rural people and encouraging them to conduct more digital transactions. With efforts underway for integrating financial education modules in the school curriculum across the country, it is also essential to complement the course curriculum through co-scholastic approaches wherein the children are encouraged to learn financial literacy concepts through relevant activities which have the ability to result in better engagement and superior retention. The NCFE's Money Smart School Programme encourages school students to enhance their financial knowledge as a key life skill and use them in their daily life. All financial education initiatives targeting students should include practical aspects through iterations to ensure retention of the various concepts.

Chapter 3: Assessment of the Needs and Critical Gaps

3.1 To prepare a comprehensive Strategy based on people's needs and the country's available resources, the following process has been adopted in the Indian context:

- A. Assessing and evaluating gaps in financial literacy.
- B. Comparison of NSFE with the OECD-INFE Policy Handbook on National Strategies for Financial Education

A. Assessment and Evaluation of Critical Gaps in Financial Literacy

3.2 NCFE has carried out an All India Financial Inclusion and Financial Literacy Survey in 2019 with the help of an external surveying agency to find out the status of financial literacy in India. It may be mentioned that a similar Survey was undertaken in 2013 on the lines of OECD-INFE toolkit. A sample of 75000 adults aged 18 to 79 were interviewed in 14 national/regional languages using a set of household questionnaire. A multi-stage sampling technique has been adopted for selection of districts, block/wards, villages, households, respondents during the Survey.

Box Item 2: OECD-INFE Definition of Components of Financial Literacy

Financial literacy encompasses aspects of knowledge, attitude and behaviour covering the range of context such as money management, planning for short and long term financial goals and awareness and choice of financial products.

Financial Knowledge involves understanding of key financial concepts and ability to evaluate benefit in real life financial situations. The concept of simple interest, compound interest, time value of money, inflation, diversification, division, risk-return and interest paid on loan are tested to determine the financial knowledge of an individual.

Financial Behaviour involves study of day-to-day money management, financial planning, spending, savings, investment, reliance on credit to meet daily requirement and building a safety net for future well-being.

Financial Attitude aims at studying people's response towards savings, prioritization of short-term wants over long-term security, inclination towards risk, et al. for future well-being.

3.3 The Survey conducted in 2019 revealed that 27.18 % of the respondents have achieved minimum target score/minimum threshold score in each of the components of financial literacy prescribed by OECD-INFE [i.e. a minimum of 3 in Financial Attitude (out of 5), 6 in Financial Behaviour (out of 9) and 6 in Financial Knowledge (out of 9)] as compared to 20% in 2013.

3.4 Some of the major findings of the Survey are illustrated in the charts below:

Chart 1: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Gender-wise

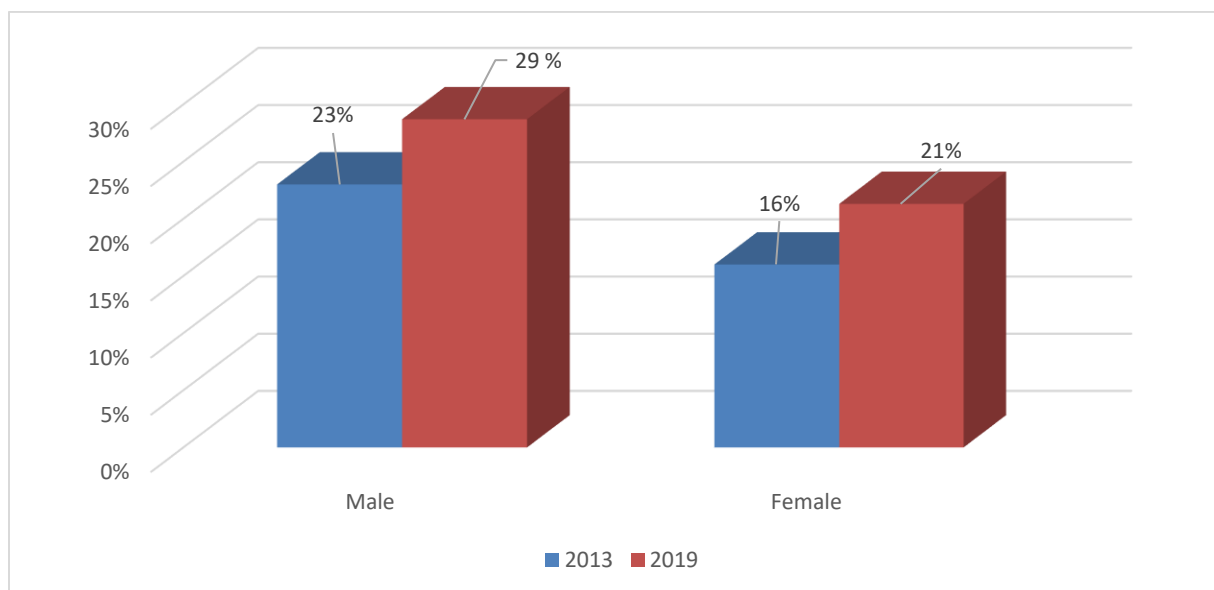


Chart 2: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Zone-Wise

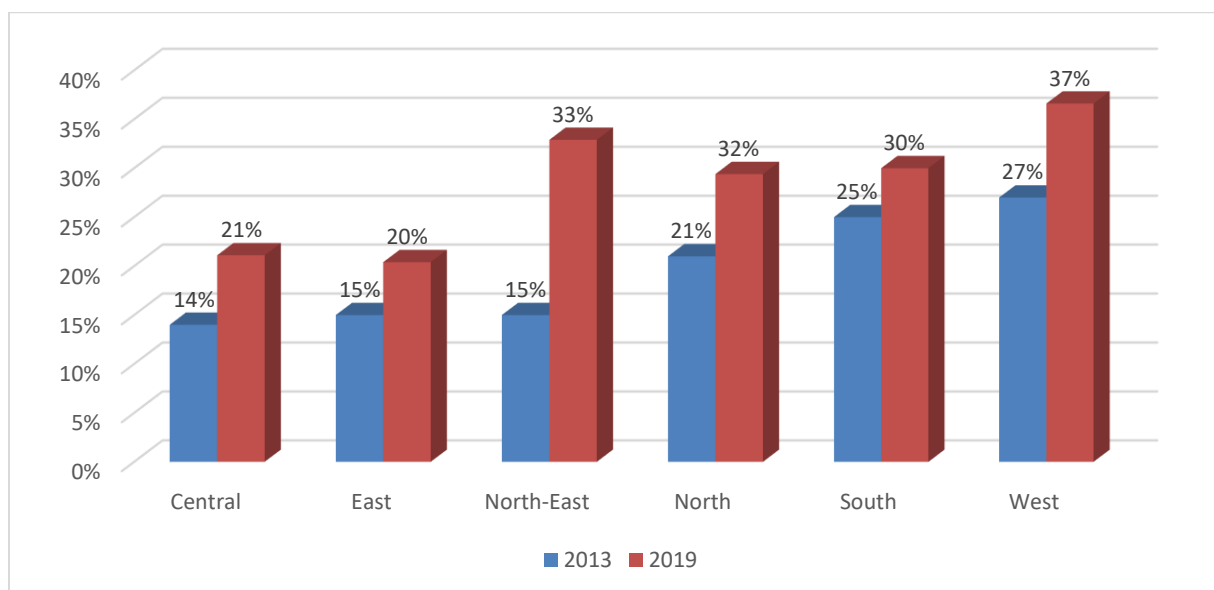


Chart 3: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Occupation-wise

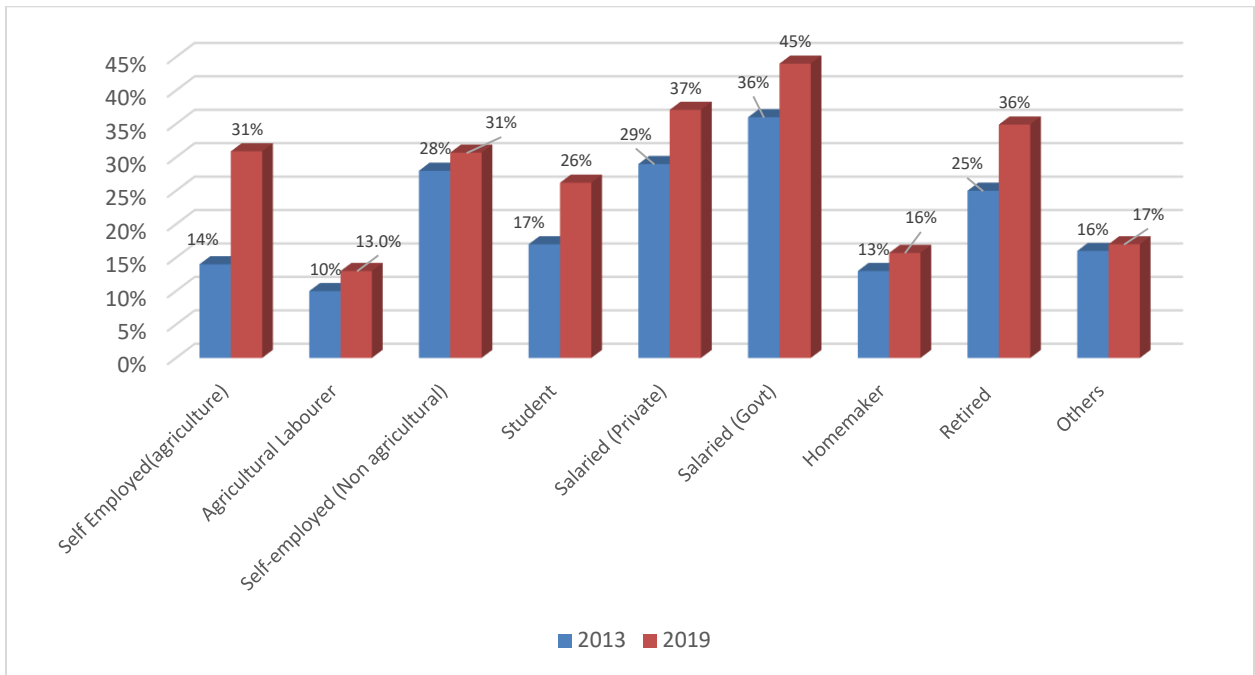


Chart 4: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Annual Income-wise

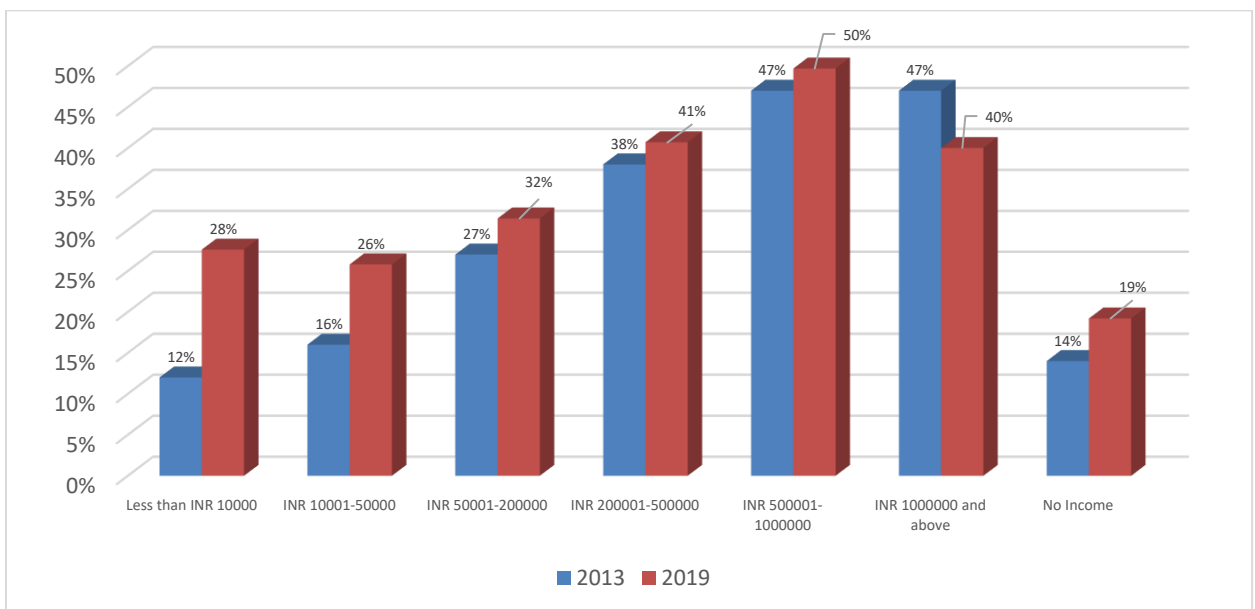


Chart 5: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Rural-Urban

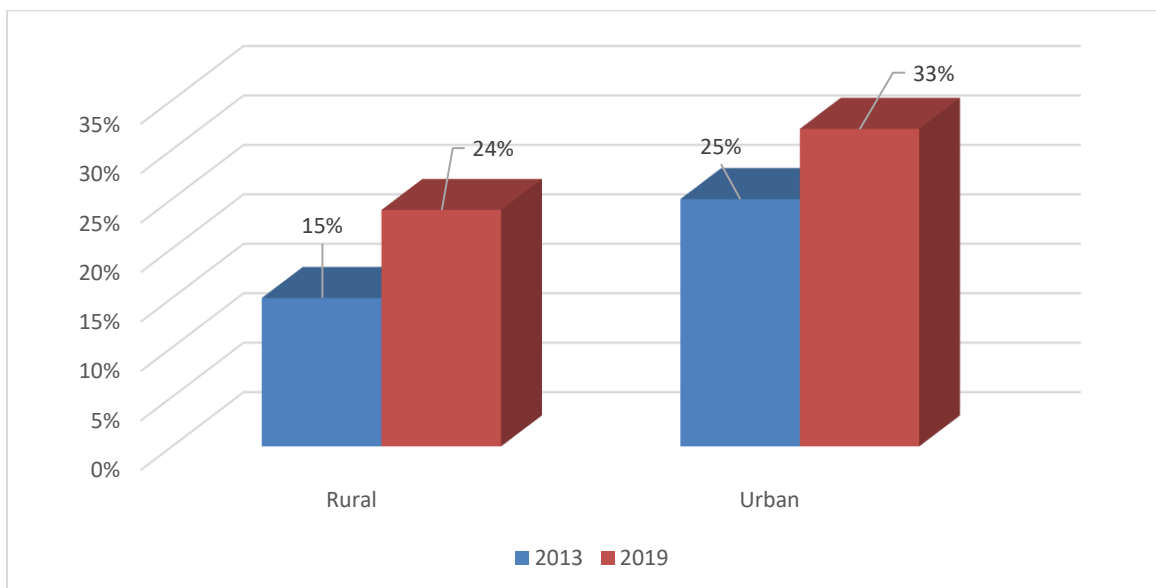


Chart 6: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Education-wise

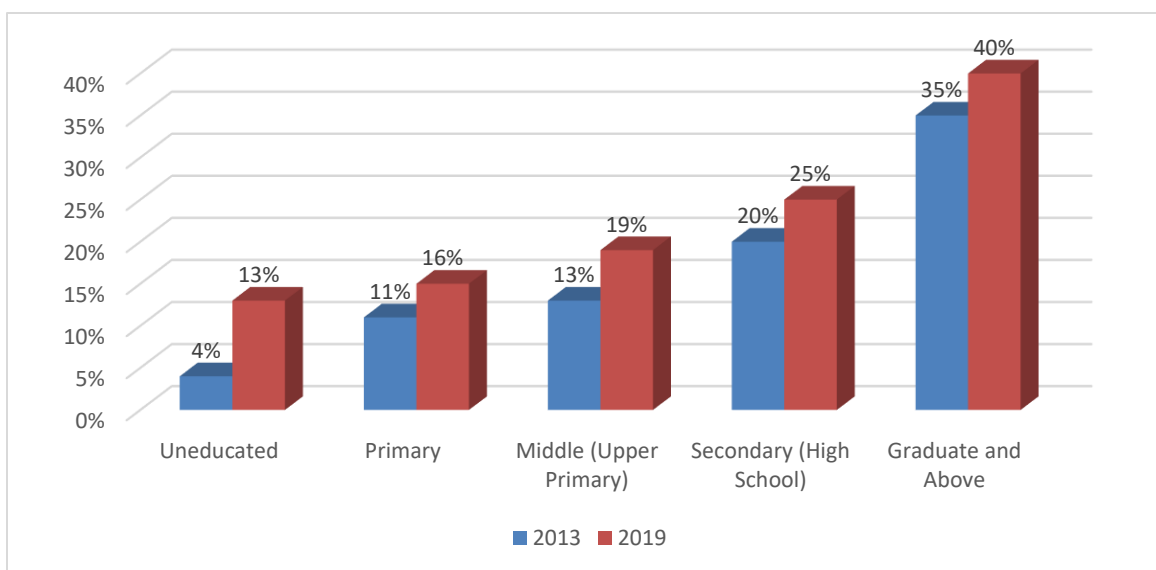


Chart 7: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Social Category-Wise

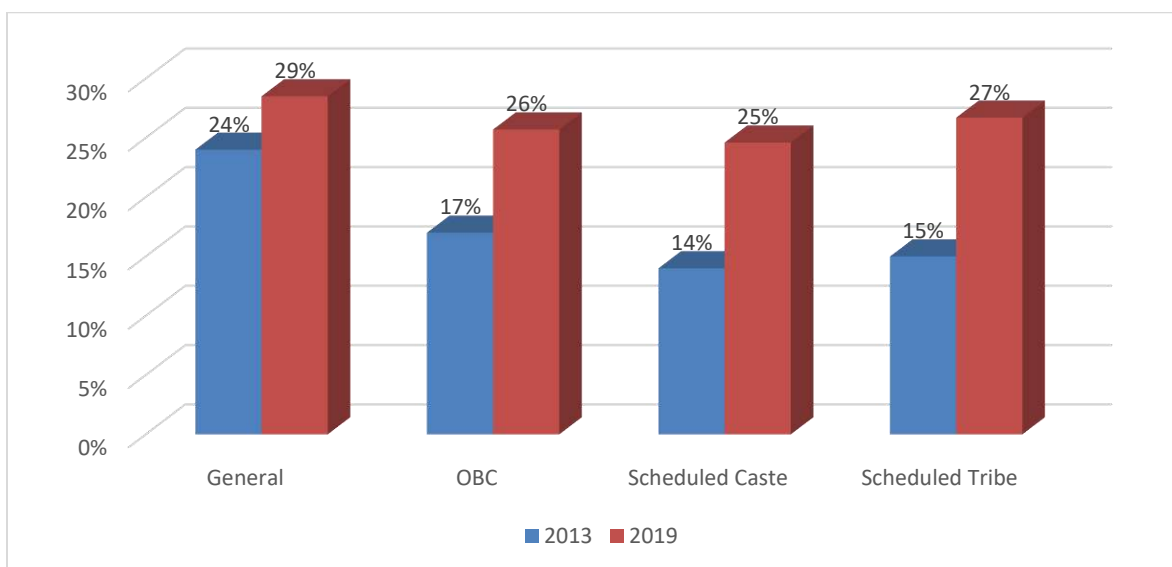
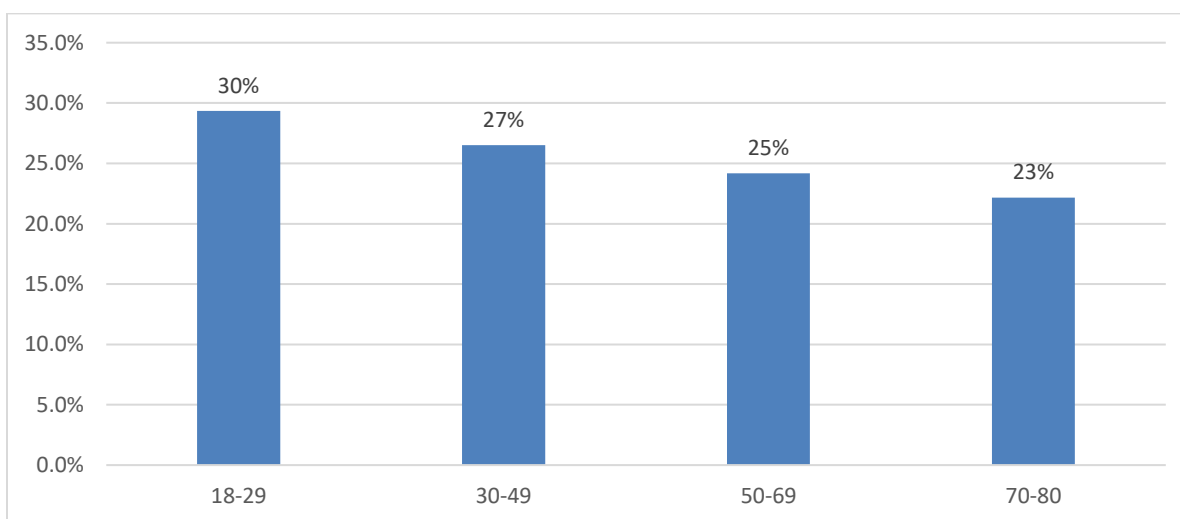


Chart 8: Percentage of Population Crossing the Minimum Threshold Score
Age Wise (2019)



3.5 Based on the above illustrative Charts, the following thrust areas have been arrived at for improving financial education efforts:

- i. Though there has been an improvement over the period, further efforts are needed to improve financial literacy among women
- ii. East, Central and North Zone need more attention⁵

⁵ In the survey undertaken in 2013, North East Zone was subsumed under East Zone. Hence the data for North East between 2013 and 2019 may not be comparable.

- iii. Rural India needs focused attention
- iv. The group with lower education needs greater financial education initiatives
- v. The group of age '50 and above' needs more financial education

B. Comparison of NSFE with the OECD-INFE Policy Handbook on National Strategies for Financial Education

3.6 The OECD-INFE Policy Handbook on National Strategies for Financial Education (OECD, 2015) lays down important broad guidelines for Nations to develop their National Strategies for Financial Education. Based on the Handbook, the following steps have been undertaken by adopting them in the Indian context to develop the country's Strategy:

I. Identification of Policy Priorities of the National Strategy through the Tools of Assessment

- a) **Mapping exercise of existing initiatives:** Keeping in view the developments over the last five years since the launch of the first National Strategy for Financial Education (2013-2018) and the emerging aspirations of the country, NCFE had undertaken a mapping exercise of existing initiatives through consultation with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India; Financial Sector Regulators; Banks; Development Financial Institutions; Indian Banks' Association; Self-Regulatory Organizations (SROs) (FIDC, M-Fin and Sa-Dhan); and other stakeholders (such as NPCI). The key initiatives taken by NCFE, the Financial Sector Regulators, Development Financial Institutions, NPCI, etc. are summarized in Annex. The key learnings from these initiatives along with a study of global best practices on financial education have been used in formulating the strategic objectives and developing the action plans.
- b) **Measurement of Level of Financial Literacy and Inclusion through Nation-wide Survey:** A Pan India Financial Inclusion and Financial Literacy Survey in line with the standards prescribed by OECD-INFE toolkit was undertaken in 2013-2014 to assess the level of financial literacy in the country. Subsequent to the completion of the period of the 1st NSFE, a survey has been undertaken in 2019 to empirically review the progress made during the last five years (2013-2018).

II. Establishing Institutional and Governing Arrangements

Keeping in view the existing institutional arrangement for guiding, monitoring and evaluating the Strategy, a well-defined institutional arrangement has been developed and laid down in Chapter 6.

III. Evaluation Plan of National Strategy for Financial Education

A standardized method to monitor and evaluate the progress made by various stakeholders under the period of the Strategy has been laid down in Chapter 7.

Chapter 4: Vision and Strategic Objectives of NSFE (2020-2025)

4.1 As mentioned in the document titled - *Advancing National Strategies for Financial Education*, (jointly published by OECD and Russia's G20 Presidency in 2003), it is essential to establish clear financial education mandates, objectives and resources to be deployed by relevant public institutions for advancing National Strategy for Financial Education.

4.2 This Strategy document has been developed as a revised version of its precursor, NSFE (2013-2018) by including data-driven findings, new policy measures, evaluation tools, interventions and technological improvements. Since this Strategy is a revision of the earlier Strategy, *it has been decided to retain the Vision and merge the Mission with the following Strategic Objectives.*

Vision – A financially aware and empowered India

4.3 As there have been several developments in the financial inclusion landscape and the economy, in general, the Strategic Objectives have been revised to reflect the changes in the vast economic landscape and provide renewed impetus to promote financial education in the vast expanse of the diverse country.

The Strategic Objectives are as under:

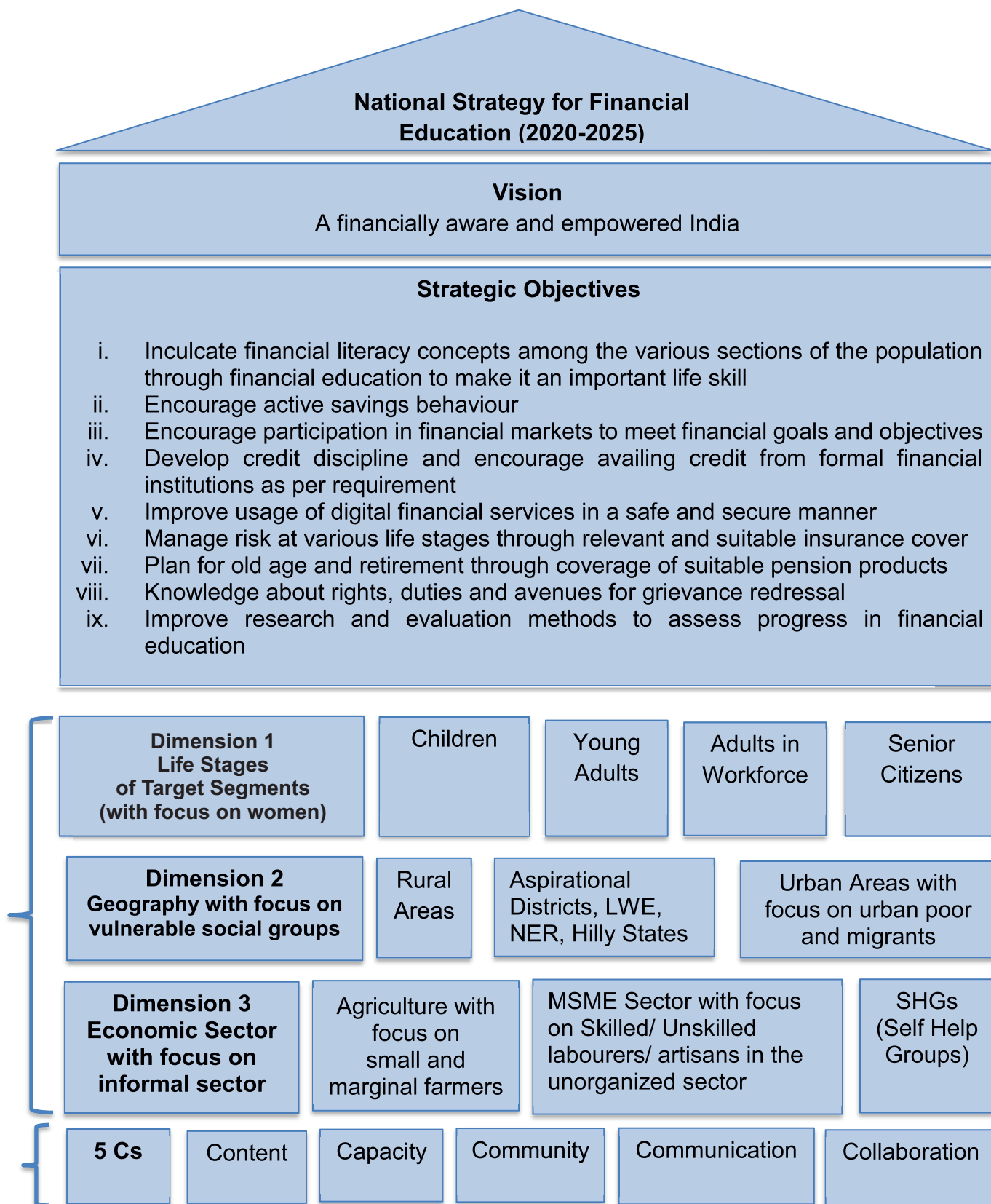
- i. Inculcate financial literacy concepts among the various sections of the population through financial education to make it an important life skill
- ii. Encourage active savings behaviour
- iii. Encourage participation in financial markets to meet financial goals and objectives
- iv. Develop credit discipline and encourage availing credit from formal financial institutions as per requirement
- v. Improve usage of digital financial services in a safe and secure manner
- vi. Manage risk at various life stages through relevant and suitable insurance cover
- vii. Plan for old age and retirement through coverage of suitable pension products
- viii. Knowledge about rights, duties and avenues for grievance redressal
- ix. Improve research and evaluation methods to assess progress in financial education

4.4 Keeping in view the importance of granularity and our learning that a one-size-fits-all approach to financial education does not yield the desired results, the Strategic Objectives are envisaged to be achieved through the following dimensions:

Sl. No	Dimension	Brief Description
1	Life Stages of Target Segments	Children, young adults, adults in workforce, senior citizens- with special focus on women
2	Geography with focus on vulnerable social groups	Rural, Urban (with focus on urban poor and migrants), Aspirational Districts, LWE, North Eastern Region (NER), Hilly States, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep with focus on vulnerable social groups, migrants, persons with disabilities (Divyangjan)
3	Sector specific focus	Agriculture, Manufacturing (Skilled/Unskilled labourers/artisans under MSME Sector, members of SHGs), Self Employed/ Unorganized sector

4.5 A '**5 C**' approach would be adopted for dissemination of financial education through emphasis on development of relevant **Content** (*including Curriculum in schools, colleges and training establishments*), developing **Capacity** among the intermediaries involved in providing financial services, leveraging on the positive effect of **Community** led model for financial literacy through appropriate **Communication** Strategy, and lastly, enhancing **Collaboration** among various stakeholders.

Figure 1: Vision & Strategic Objectives of NSFE (2020-2025)



Chapter 5: Policy Design

5.1 Components of Financial Education

5.1.1 Basic Financial Education

The basic financial education consists of fundamental tenets of financial well-being⁶. With the introduction of Government's PMJDY scheme along with APY, PMJJBY & PMSBY besides MUDRA Yojana, many people have already been included. They also require financial education so that they can take full benefits from these schemes. These basic concepts need to be communicated to everyone by adopting different modes of delivery, suitable to the target audience. Special emphasis shall be laid on the financially excluded and those newly included but not operating their accounts. The basic financial education acts as a foundation for sector-specific and process education.

5.1.2 Sector Specific Financial Education

Sector specific financial education is being imparted by the Financial Sector Regulators and focuses on "What" of the financial services and the contents cover awareness on 'Dos & Don'ts', 'Rights & Responsibilities', 'Safe usage of digital financial services' and approaching 'Grievance Redressal' Authority.

Basic and Sector specific education will empower a person to be more prudent and make informed decisions while choosing appropriate financial products as per his/ her requirements from the available alternatives.

5.1.3 Process Education

Process education is crucial to ensure that the knowledge translates into behavior. As an illustration, some of the aspects to be covered include:

- How to use an ATM card?
- How to do an UPI Transaction?
- How to deposit money with a BC?
- How to fill a loan application form?
- How to compare and select an appropriate loan product?
- How to purchase an insurance cover?
- How to do various transactions in securities markets?
- How to allocate funds in a pension plan?

⁶ The concepts include: (a) importance and advantages of savings, (b) staying out of unproductive loans, (c) borrowing from formal financial sector as per need and capacity, (d) interest rate and the power of compounding, (e) time value of money, (f) inflation, (g) the need to insure, (h) the need to plan for old age income, (i) role of major financial sector related institutions such as Ministries, Financial Sector Regulators, banks, stock exchanges and insurance companies and (j) basic concept regarding relation between risks versus returns, (k) grievance redressal.

- How to lodge a complaint with the financial service provider?
- How to approach an Ombudsman/Grievance Redressal Authority, etc.

These contents are to be developed in the form of easy to understand Audio/ Video, Animated Posters to help the consumers understand the processes to be adopted for various transactions. *(For example, a short video on how to use the ATM displayed in the ATM machine would be helpful for a customer to avail the service)*

5.2 Delivery Channels for Financial Education

Besides the already existing delivery channels for disseminating financial education messages, newer modes of delivery channels such as social media platforms, community radios, technology kiosks, chatbots etc. shall be effectively deployed.

Chapter 6: Action Plan to Achieve the Strategic Objectives

6.1 The **5-Core Actions / 5-C Approach** shall be adopted through emphasis on development of relevant **Content**, developing **Capacity** of the various intermediaries involved in providing financial services, leveraging on the facilitating role of **Community** led model for financial literacy through appropriate **Communication** strategy by enhancing **Collaboration** among various stakeholders. A brief about each of the following core actions is given below.

6.1.1 Content

- Financial Literacy content for school children (including curriculum and co-scholastic), teachers, young adults, women, new entrants at workplace/ entrepreneurs (MSMEs), senior citizens, persons with disabilities, illiterate people, etc

6.1.2 Capacity

- Develop the capacity of various intermediaries who can be involved in providing financial literacy
- Develop a 'Code of Conduct' for financial education providers

6.1.3 Community

- Evolve community led approaches for disseminating financial literacy in a sustainable manner

6.1.4 Communication

- Use technology, mass media channels and innovative ways of communication for dissemination of financial education messages
- Identify a specific period in the year to disseminate financial literacy messages on a large scale
- Leverage on Public Places with greater visibility (e.g. Bus Stands, Railway Stations, etc.) for meaningful dissemination of financial literacy messages

6.1.5 Collaboration

- Preparation of an Information Dashboard
- Integrate financial education content in school curriculum, various Professional and Vocational courses (undertaken by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSD&E) through their Sector Skilling Missions and the like of B.Ed./M.Ed. programmes)
- Integrate financial education dissemination as part of various on-going programmes
- Streamline efforts of other stakeholders for financial literacy

6.2 The Strategic Goals along with detailed implementation plan and milestones are detailed in the following pages.

Action Plan for NSFE (2020-2025)

5 Cs	Sr No	Strategic Goal	Implementation Plan	Milestone	Action By
Content	1	Develop financial literacy content for school children (including curriculum and co-scholastic), teachers, young adults, women, new entrants at workplace/ entrepreneurs (MSMEs), senior citizens, persons with disabilities, illiterate people etc	Development of content that can be delivered through audio-video, print, mass media, digital format etc. with specific target audience orientation (e.g. teachers, school children, young adults, women, new entrants at workplace/ entrepreneurs (MSMEs), senior citizens, illiterate people etc.). The content which inter-alia shall include digital financial services should be in regional languages with active inclusion of local phrases/dialects to promote better reach and feel among the target audiences	March 2021	NCFE, All the Financial Sector Regulators, SIDBI and NABARD
			Update content of financial education in school curriculum for students of Classes VI to X	March 2021	NCFE and All the Financial Sector Regulators
			Make financial literacy content accessible for persons with disabilities (Divyangjan) etc	March 2021	NCFE, All the Financial Sector Regulators and MSJ&E
			Develop content for financial awareness among students of higher classes (Classes XI-XII) through co-scholastic approaches and reinforcing financial literacy as an integral part of vocational education (ITI/Poly-Technical courses etc)	March 2022	NCFE, MSD&E and MHRD

Capacity	1	Develop the capacity of various intermediaries who can be involved in providing financial literacy	Develop the capacity of FLC Counsellors, SEBI's Resource Persons, Rural Branch Managers etc to become important vehicles for dissemination of financial literacy	March 2022	NCFE and All the Financial Sector Regulators
			Improve the competence of Master Trainers of NRLM through refresher programmes to keep them updated on the latest developments in the financial sector	March 2022	NCFE, MoRD and NABARD
			Strengthen the capacity of SHG leaders, Bank Sakhis, who can help in dissemination of financial literacy	March 2022	NCFE, NABARD, MoRD, RBI and SEBI
			Strengthen the capacity of Secondary School teachers (classes VI-X) who can disseminate financial literacy content	March 2022	NCFE and MHRD
	2	Develop a Code of Conduct for financial education providers	A Voluntary Code of Conduct for financial education providers to be developed	March 2021	All the Financial Sector Regulators and NCFE
Community	1	Evolve community led approaches for disseminating financial literacy in a sustainable manner	Evolve community led approaches for encouraging volunteers, local SHGs, field level functionaries, teachers and community ambassadors to become agents for disseminating financial literacy	March 2021	NCFE, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development, NABARD and

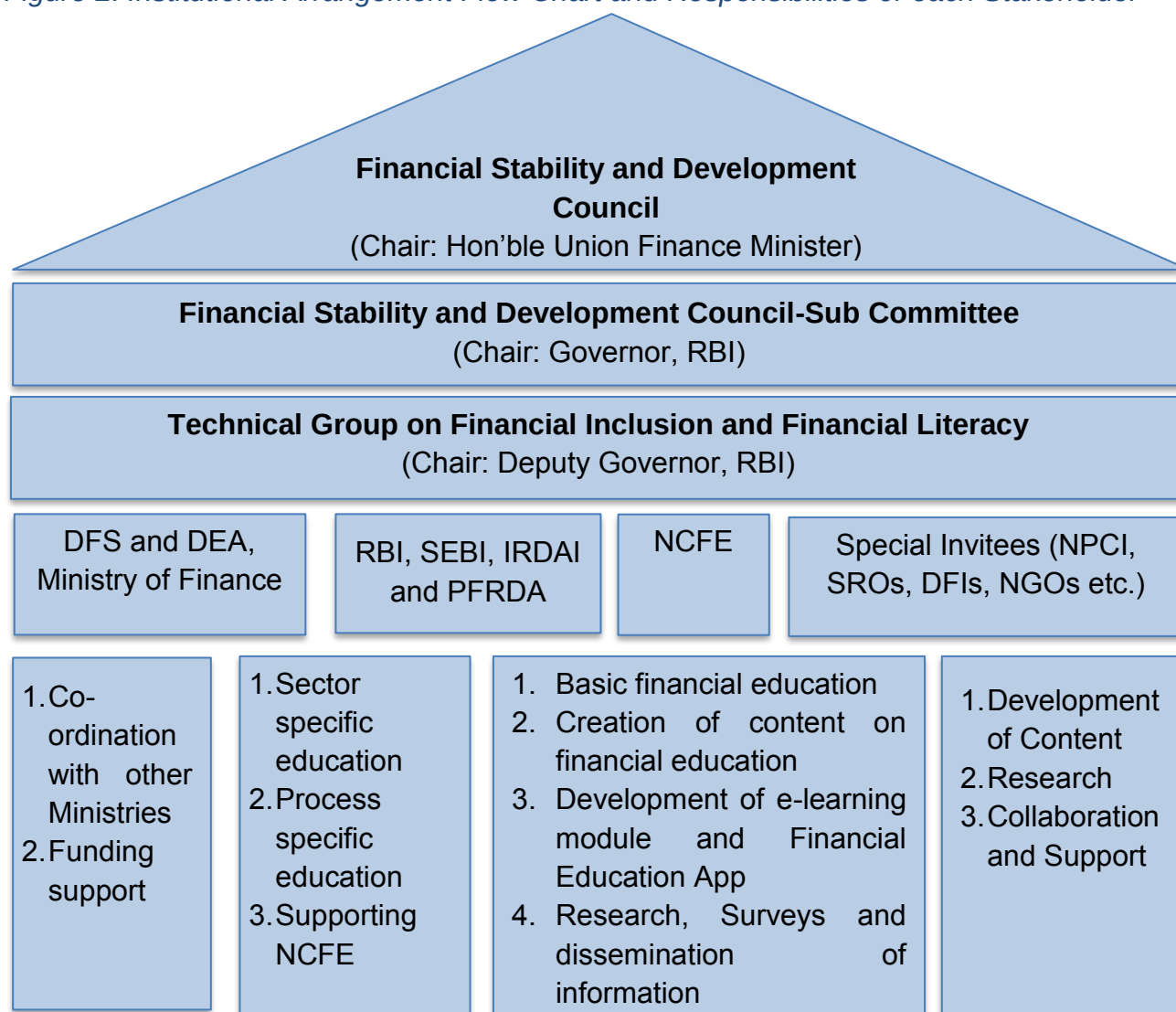
					State Governments
			Utilize the services of Anganwadi workers, ASHA workers, Post Men etc. to become agents for mobilizing people to approach formal financial service providers, BCs, CFLs, FLCs, etc	March 2023	NCFE, IPPB, Ministry of Women and Child Development and Ministry of Health and Family Welfare
			Undertake Financial Education Program for Adults (FEPA) in underbanked districts and aspirational districts of the country through targeted campaigns under community led approaches	March 2022	NCFE, Ministry of Panchayati Raj and State Governments
Communication	1	Use technology, mass media channels and innovative ways of communication for dissemination of financial education messages	Display financial literacy messages in a prominent location in the website of financial sector regulators and financial service providers	March 2021	NCFE and All the Financial Sector Regulators
			Develop a financial literacy mobile app	March 2021	NCFE
			Develop a common toll-free number to provide information on the procedures to be adopted for redressal of grievances	March 2022	NCFE and All the Financial Sector Regulators
			Leverage Social Media, digital kiosks to disseminate financial literacy messages	March 2021	NCFE and All the Financial Sector Regulators

			Explore development of chatbots to respond to common consumer queries on financial education	March 2021	NCFE and All the Financial Sector Regulators
	2	Identify a specific period in the year to disseminate financial literacy messages on a large scale	Observe a Financial Literacy Week during the year on the lines of the Financial Literacy Week being currently observed by RBI	March 2021	NCFE and All the Financial Sector Regulators
			<i>A Digital Financial Services Day</i> to be observed once a year to bring focused awareness among the masses	March 2021	MeiTY, NCFE and All the Financial Sector Regulators
	3	Leverage on Public Places with greater visibility (e.g. Bus Stands, Railway Stations, etc.) for meaningful dissemination of financial literacy messages	Displaying relevant financial literacy messages in specific public places with greater visibility like Bus Stands, Hospitals, Gram Panchayat Office, Railway Stations, Airports, Common Service Centres (CSC), buses, trains, etc	March 2023	NCFE, All the Financial Sector Regulators and Corporates undertaking CSR activities
Collaboration	1	Preparation of an Information Dashboard	Prepare a Digital Repository containing details of financial literacy programmes conducted by various stakeholders which would be an information Dashboard on Financial Literacy Programs	March 2021	NCFE
	2	Integrate financial education content in school curriculum,	Integrate financial education in courses like B.Ed./M.Ed. besides other Teachers' training courses to create a cadre of	March 2023	NCFE and UGC/ MHRD

		various Professional and Vocational courses (undertaken by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSD&E) through their Sector Skilling Missions and the like of B.Ed./M.Ed. programmes)	financially educated teaching professionals		
			Integrate financial literacy modules in the various training programmes undertaken by MSD&E through their Sector Skilling Missions	March 2025	NCFE, All the Financial Sector Regulators and MSD&E
			Integrate financial education in school curriculum for students of Classes VI to X	March 2022	NCFE, MHRD, Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) and State Governments
	3	Integrate financial education dissemination as part of various on-going programmes	Delivery of financial education for newly inducted people in the financial system	March 2022	NCFE
	4	Streamline efforts of other stakeholders for financial literacy	NCFE to explore strategic partnerships among Government Bodies which are involved in providing financial education	March 2021	NCFE
			Industry Associations, Self-Regulatory Organizations (SROs) and other intermediaries of financial sector (like IBA, FEDAI, AMFI, BCFI, MFIN etc.) to be entrusted upon the role of conducting financial education programs	March 2022	NCFE and All the Financial Sector Regulators

The intervention of Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India would be sought for implementation of the above Action Plans, as and when necessary.

Figure 2: Institutional Arrangement Flow Chart and Responsibilities of each Stakeholder



6.3 In line with the previous Strategy, the entire National Strategy for Financial Education (2020-2025) is sought to be implemented through the institutional mechanism, as illustrated above. Besides the oversight of the FSDC (Chair: Hon'ble Union Finance Minister), the implementation of the Strategy would be directly monitored by the Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL) (Chair: Deputy Governor, RBI).

6.4 Since the implementation of the National Strategy for Financial Education would entail large allocation and deployment of financial resources and manpower, adequate planning needs to be done at the Apex as well as at the level of Sector Specific Financial Regulators to ensure smooth implementation. All the Financial Sector Regulators, their respective Regulated Entities and other stakeholders should make necessary provisions for the same.

6.5 Identification of Key Stakeholders in the National Strategy: The following stakeholders have been identified for implementation of the strategic goals. The list is illustrative and not exhaustive.

- i. Government of India: Department of Financial Services (Ministry of Finance), Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Rural Development/ National Rural Livelihood Mission, Ministry of Urban Affairs and Poverty Alleviation/ National Urban Livelihood Mission, Ministry of Human Resources Development, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Social Justice and Empowerment
- ii. Financial Sector Regulators: RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA
- iii. National Centre for Financial Education (NCFE)
- iv. Development Financial Institutions: NABARD and SIDBI
- v. Industry Associations: IBA, AMFI, FEDAI, BCFI
- vi. Securities Market Institutions Infrastructure: Stock Exchanges, Depositories
- vii. Payment Institutions: NPCI
- viii. Investor Education Institutions: IEPFA, IICA, etc
- ix. Financial Service Providers: Banks, Insurance Companies, Mutual Fund Companies, Pension Funds, Stock Exchanges and Depositories, Non-Banking Financial Companies, Fin-tech companies, etc
- x. Self-Regulatory Organizations (SROs): FIDC, M-Fin, Sa-Dhan, etc
- xi. State Rural Livelihood Mission (SRLM) of all states
- xii. NGOs/ Civil Society Organizations
- xiii. Research Institutions
- xiv. Consumer Associations
- xv. Multi-Lateral Institutions (OECD-INFE, G20, etc.): For knowledge sharing on Global Best Practices

Box Item 3: Technology and Civil Society for Improving Financial Literacy

PMJDY and the PMJJBY/ PMSBY (Micro-insurance), Over-Draft (OD) of PMJDY (Micro credit) and MUDRA Scheme (MSME/ Non-farm credit) and APY (Micro pension) are important Government initiatives to improve financial inclusion and thereby create an equitable society. It is well known that financial literacy is central to ensure that the accounts opened through financial inclusion efforts are used by the people by availing products/ services relevant to them. To bridge the gap in financial literacy, there is a strong case for exploring strategic partnerships among various stakeholders, based on their individual core competencies. A case in point is the potential collaborations between Technology companies (Fin-Tech) and Philanthropy Organizations/ Civil society who can synergize their efforts to improve financial literacy among various target audience (For instance, school children in rural areas, youth in aspirational districts and women in LWE districts). While the broad contours of the content can be provided centrally, the local NGOs who have a good knowledge of the grass root realities of the communities, can customize it and make it relevant to the target audience and disseminate the same through local resources. Currently, such processes are adopted by a few organizations to achieve scale, efficiency and effectiveness in imparting financial literacy across the country. Reserve Bank of India's Pilot CFL project, MeITY's Digital Literacy Programme, NCFE's Money Smart Schools programme are some of the examples of involving stakeholders from the community to strengthen dissemination of financial literacy.

Chapter 7: Monitoring and Evaluation

7.1 It is well known that any Strategy is as good as its implementation. Keeping in view the vast and rapid changes taking place in the financial sector, all the stakeholders need to appreciate the dynamic nature of evolution of financial services and the concomitant changes that are required towards financial literacy. Having in place, a robust and scientific assessment method, would go a long way in helping Policy makers identify priorities and assess the impact of their interventions.

7.2 Some of the broad issues that need to be considered in this regard are as under:

- i. National Strategy evaluation will include an assessment of the governance, co-ordination and monitoring mechanisms of the implementation methods, the role of stakeholders and the effects of any communication or publicity plans/ initiatives.
- ii. Each stakeholder needs to clearly plan and articulate their role in the design, development and implementation of the Strategy which shall be monitored through qualitative and quantitative indicators.
- iii. A scientifically designed template for gathering feedback through various channels, from both the beneficiaries of financial literacy programmes and the intermediaries involved in disseminating the same, needs to be prepared and periodically reviewed keeping in view the vast changes in the financial sector.
- iv. Selection of appropriate evaluation methods need to be finalized in view of the challenges involved in evaluation.

7.3 The OECD-INFE Issue Note on the Evaluation of National Strategies for Financial Education suggests that evaluation of National Strategy is essential from an accountability perspective, to provide valuable evidence to improve financial education policies and contribute to their sustainability, on the long term besides being a powerful source of evidence for the impact on the financial literacy and financial behaviour of citizens. The document also distinguishes between monitoring (*A process of regular tracking of the implementation process*) and Evaluation (*The comprehensive process of understanding how the National Strategy has advanced towards its objectives*) (OECD, 2019).

Monitoring Mechanism

7.4 The Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL)(Chair: DG, RBI) shall be responsible for periodic monitoring and implementation of National Strategy for Financial Education. There would be periodic monitoring of the activities undertaken by various stakeholders for dissemination of basic, sector specific and process literacy. A Digital Repository to collect information on various financial literacy activities undertaken by the stakeholders shall be prepared. To begin with, the Digital Repository can collect data of NCFE's financial literacy initiatives, the Financial Sector

Regulators and over time, gather data from Development Financial Institutions (NABARD and SIDBI), financial service providers and other stakeholders. Based on analyses and feedback from the participants, this Digital Repository would help in identifying those areas/geographies where more financial education interventions would be needed and at the same time, prevent duplication of efforts by stakeholders.

Evaluation Mechanism

7.5 Evaluation of the Strategy refers to a process that is seeking to assess if, and How, the National Strategy is adding value, Whether it is meeting its objectives and What impact it is having on the stated aims (OECD, 2019). Proper evaluation provides feedback as to whether the Strategy is leading to a change that is desirable and a change which would not have occurred, otherwise. The OECD-INFE Issue Note on the Evaluation of National Strategies for Financial Education Monitoring highlights the importance of integrating the evaluation process in the Strategy document and ensuring that the co-ordinators actively engage with evaluation across short-term, medium-term and long-term time horizon and using the data collected through monitoring process and undertaking analysis of the same.

7.6 Keeping this in view, a Mid-term Evaluation shall be undertaken at the end of three years of Strategy implementation (2022-2023). A comprehensive National Survey at the end of the Strategy implementation period shall be undertaken in 2025.

References

1. (2003). *Advancing National Strategies for Financial Education*. OECD and Russia's G20 Presidency joint publication.
2. Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. (2019, October 24). *Progress Report-PMJDY*. Retrieved from Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: <https://www.pmjdy.gov.in/account>
3. NCFE-NISM. (2013). *Financial Literacy and Inclusion in India - Final Survey Report 2013*. Mumbai: NCFE-NISM.
4. OECD. (2005). *Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies*, OECD Publishing.
5. OECD. (2005). *Recommendation of Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness*. Paris: OECD.
6. OECD. (2012). *High-level Principles on National Strategy for Financial Education*.
7. OECD. (2015). *National Strategies for Financial Education-OECD/INFE Policy Handbook*. Paris: OECD.
8. OECD. (2016). *OECD/INFE International Survey of adult financial literacy competencies*. Paris: OECD.
9. OECD. (2019). *Evaluation of National Strategies for Financial Education*. Paris: OECD-INFE.
10. Rangarajan, D. C. (2008). *Committee on Financial Inclusion*. Mumbai: RBI.
11. World Bank Group. (2018). *The Global Findex Database*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Annex - Financial Literacy Initiatives by Stakeholders

A. NCFE

NCFE creates financial awareness and empowerment through financial education campaigns across the country for all sections of the population through seminars, workshops, conclaves, trainings, programs, campaigns, discussion forums by itself or with help of institutions, organizations and provide training in financial education. It creates workbooks, worksheets, literature, pamphlets, booklets, fliers, technical aids. NCFE prepares appropriate financial literature for target-based audience on financial markets and financial digital modes for improving financial literacy so as to improve their knowledge, understanding, skills and competence in finance.

Basic Financial Education: NCFE is conducting financial education campaign through financial education programs like MSSP (for schools), Financial Education Training Programme (FETP) for school teachers, FACT (for undergraduate and postgraduate students) and FEPA (financial education program for adults).

- a. Money Smart School Program (MSSP) is an academic year program where schools voluntarily implement financial education as part of school curriculum.
- b. NCFE–National Financial Literacy Assessment Test (NFLAT) is a first kind of national level test, conducted by the NCFE, to measure the level of financial literacy among school students.
- c. FETP is an initiative for providing unbiased personal financial education training to school teachers to facilitate inclusion of financial education in school curriculum. With the success of NFLAT, there was a requirement to train the school teachers in the areas of financial education so that they in turn can conduct classes and help school students acquire basic financial literacy skills.
- d. FACT (Financial Awareness and Consumer Training) is a program by NCFE to provide financial education to young graduates and postgraduates, on topics relevant to them, which will positively impact their financial wellbeing.
- e. Financial Education Program for Adults (FEPA) is a new initiative started by NCFE. FEPA is aimed at providing basic financial education to the adult section of underserved areas of India, especially rural India.

B. RBI

Basic Financial Education: RBI has prescribed the following content for basic financial education:

- a. Financial Literacy guide, Financial Diary and set of 16 posters prepared by RBI

b. Special camps booklet prepared by NCFE for people newly inducted into the financial system which captures the fundamental tenets of financial wellbeing such as savings, borrowings, concept of interest and compounding, time value of money, inflation, relation between risk and rewards etc.

Sector Focused Financial Education: The content covers relevant topics in the banking sector such as ATMs, payment systems such as NEFT, UPI, USSD, awareness about sachet portal, keeping away from Ponzi schemes, fictitious emails/calls, KYC, Exercising Credit Discipline, Business Correspondents etc. A Financial Awareness Messages (FAME) booklet comprising of 20 messages for the general public and five Posters on financial literacy for the Financial Literacy Week have been made available on the Financial Education webpage of RBI's website.

Public Awareness Campaign

- Important press releases, statements, regulatory guidelines, speeches, clarifications and events are tweeted on RBI's twitter handle '@RBI' and videos are relayed on RBI's YouTube link. A separate Twitter handle '@RBI says' and Facebook page 'RBI Says' publish messages and information of interest for greater awareness and understanding of the Bank's functions. Reserve Bank of India envisages limited two-way communication and engagement over social media and monitors its social media presence.
- Over the years, RBI is constantly reaching out to the common man through outreach programmes, financial literacy initiatives, space in mass media and social media platforms, etc. Reserve Bank of India also empowers the members of public by informing them about facilities and services to expect from banks and financial institutions through 'Public awareness campaign' which aims to educate the members of public regarding their rights and responsibilities in banking related matters. The campaigns are done on a regular basis in newspaper, TV, Radio, Cinema, Digital channels, SMS and hoardings, under the tagline 'RBI Kehta Hai'.
- For the video spots, at present, some cricketers and badminton players who are employees of the Reserve Bank of India and also are a part of various IPL/PBL teams have been roped in. The stories in these video spots work at many levels. Apart from the main message, the story line also builds an immediate emotional connect with the audience and the conversational script helps keep human interest alive in a dry subject like nitty gritty of a bank account.
- The public awareness campaign of the Reserve Bank of India started in 2017 and gathered steam in 2018. Advertisements on Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA), Safe Digital Banking, Limited Liability and Ease of Banking for Senior Citizens were released in popular events such as the Indian Premier League (IPL),

the 2018 FIFA World Cup, Asian Games, Kaun Banega Crorepati (KBC), Pro Kabaddi League, Pro Badminton League and India-New Zealand One Day International.

- A film on BSBDAs explains how opening of this account obviates the requirement of minimum balance. A film on Safe Digital Banking cautions the public about sharing card and PIN details while carrying out digital transactions. Another film on Limited Liability explains the recourse available in the event of card fraud. A film on 'Ease of Banking for Senior Citizens' elucidates facilities like doorstep banking available for senior citizens. These films, using cricketers and badminton players, who are employees of the Reserve Bank of India, were widely disseminated in media advertisements.
- A unique feature of the public awareness campaign is the missed call element: upon giving a missed call to the number 14440, the caller will receive information through a pre-recorded Interactive Voice Response System (IVRS), avoiding the miscommunication or over-communication of a call centre approach. In the non-Hindi speaking regions, mobile phone subscribers receive messages in English and regional languages, so that the connect with common person is immediate and all encompassing.

C. SEBI

Basic Financial Education: SEBI has undertaken the following initiatives for basic financial education:

- a. Financial Education through Resource Persons Program to impart financial education to public. The eligible individuals trained and empanelled as RPs (in districts) by SEBI who can conduct free workshops in local language and are paid honorarium. The basic concepts of finance, banking, insurance, pension and investments are covered across five Target groups (viz. Home Makers, Self-Help Groups, Executives, Middle Income Groups, Retired personnel). During the workshops, free financial education booklets are distributed
- b. Visit to SEBI by students
- c. Financial Education Booklet covering basics of concepts like Financial planning, Savings, Investment, Insurance, Pension, Borrowing, Tax saving, caution against Ponzi schemes, Grievance redressal, etc

Sector Specific Financial Education: SEBI has the following initiatives for sector focused financial education:

- a. Investor awareness programs by SEBI recognized Investors' Associations
- b. Regional Seminars in association with Exchanges/Depositories
- c. Commodity awareness programs by SEBI recognized Commodity Derivatives Trainers

In addition to the above, SEBI has also undertaken the following initiatives:

- **Participation in World Investor Week in association with International Organization of Securities Commissions (IOSCO):** With the objective of highlighting the initiatives taken by various financial market regulators in the direction of conducting investor protection and education awareness activities, IOSCO has been organizing every year a weeklong global campaign referred to as World Investor Week (WIW). SEBI participated in IOSCO WIW by organising various financial literacy and investor awareness programmes during this week across the country.
- **Dedicated Investor Website:** A dedicated website <http://investor.sebi.gov.in> is maintained for the benefit of investors. The website provides relevant educational/ awareness material and other useful information. Further, schedules of various investor and financial education programmes are also displayed on the website for the information of investors.
- **Mass Media Campaign:** In order to reach out to people, SEBI has embarked on a mass media campaign giving relevant messages to investors through popular media. Since year 2012, SEBI has carried out various awareness campaigns in multi mass media (TV/Radio/Print/bulk SMS) on topics as mentioned below:
 - Investor grievance redressal mechanism
 - Collective Investment Scheme - Unrealistic returns.
 - Collective Investment Scheme – Don't Go by Hearsay.
 - Application Supported by Blocked amount (ASBA) - Initial Public Offering (IPO).
 - Dabba Trading
 - Caution against Hot TipsAdditionally, posters on cautionary messages listed above were printed in various languages and distributed to district collectors, panchayat offices, etc. in various languages.
- **Investor Grievance Redressal:** SEBI has been taking various regulatory measures to expedite the redressal of investors grievances. The grievances lodged by investors are taken up with the respective listed company or intermediary and continuously monitored. SEBI Complaints Redressal System (SCORES) has helped the investors in real time knowledge of status of their grievances since investors can log onto SCORES at any time and from anywhere and check the status of the grievances with the help of user-name and password provided to them at the time of lodging grievances.

- **SEBI Toll Free Helpline:** SEBI had launched toll free helpline service numbers 1800 22 7575/1800 266 7575 on December 30, 2011. The helpline service is available every day from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (except on declared public holidays in Maharashtra) to investors from all over India. The helpline service is available in English, Hindi and various regional languages.

D. IRDAI

Since its inception, IRDAI has taken various initiatives in the area of financial literacy. Awareness programmes have been conducted on television and radio and simple messages about the rights and duties of policyholders, channels available for dispute redressal etc. have been disseminated through television and radio as well as the print media through sustained campaigns in English, Hindi and 11 other Indian languages.

IRDAI has got a pan India survey on awareness levels about insurance carried out through the NCAER in a bid to improve on its strategy of creating insurance awareness. A post launch survey was also done to gauge the efficacy of the campaigns of IRDAI in increasing insurance penetration and awareness. IRDAI has also brought out publications of 'Policyholder Handbooks' as well as a comic book series on insurance. A dedicated website for consumer education in insurance was launched to reach out to the policyholders more effectively. IRDAI's Integrated Grievance Management System (IGMS) creates a central repository of grievances across the country and provides for various analyses of data indicative of areas of concern to the insurance policyholder.

Some of the major initiatives carried out by IRDAI are listed below:

- Conducting seminars, awareness campaigns, Metro Rail campaigns, quizzes, etc.
- 'Young Corner'- an interactive six game featurette was launched on the Policyholders website. A Hindi version of the website was also launched to increase its reach
- Print campaign cautioning the general public about the spurious callers and fictitious offers was launched. Insurance comic books in 12 vernacular languages were released
- Handbooks on Insurance such as Employment opportunities in Insurance for students; Crop Insurance, right buying etc., were launched
- Pan-India campaign against spurious callers through TV Commercials and Radio jingles on the utility and benefits of various forms of insurance in five regional languages

E. PFRDA

PFRDA has launched a dedicated website called “Pension Sanchay” in 2018. Through this website, PFRDA aims towards addressing the need of financial literacy from the perspective of retirement planning. The content of the website has been designed keeping into view the four most important concepts in financial decision making- knowledge of interest rates, interest compounding, inflation and risk diversification. The website has separate blog segment where blogs written by the professionals in the financial sectors and the officers of the Authority are made available which provides meaningful insight regarding the fundamentals of finance, banking and investments.

PFRDA conducts subscriber awareness programs through its central record keeping agencies at different places across India. Further, PFRDA also has empaneled a dedicated training agency for creating subscriber awareness and capacity building regarding the NPS and APY. In addition to the above, PFRDA also conducts Annuity Literacy Program in co-ordination with NPS Trust and Annuity Service Providers for making subscribers aware about the different annuities available to them.

F. NABARD

- Creation of financial awareness amongst the rural masses through various media in Hindi, English and vernacular languages. (Printed materials such as leaflets, posters, books/booklets on financial literacy initiatives; jingles related to financial inclusion eg. opening of bank accounts, SHG savings, Swarojgar Credit Cards, etc., were aired and animated films on loans, budgeting and usage of ATMs hosted on our website as well as YouTube channel)
- Conduct of Financial Literacy Awareness Programmes (FLAPs) targeted for people who are newly inducted in the financial system, Adults, Farmers, School Children, Senior Citizens, SHGs and Entrepreneurs besides financial education for rural masses on different modes of digital payments.
- Conduct of FLAPs with Mobile Demo Vans fitted with Audio-Video equipment, ATM, Micro-ATM and handholding for conducting digital transactions (new point)
- Capacity building initiatives to sensitize and train the staff of commercial banks, RRBs and RCBs for effective delivery of financial literacy through BIRD Setting up of financial literacy centres by Regional Rural Banks (RRBs) and Rural Cooperative Banks (RCBs) besides deployment of mobile demonstration vans fitted with ATMs and / or Micro-ATMs
- Extended support to Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)/ Rural Development & Self Employment Training Institute (RUDSETI) to acquire training equipment for livelihood training.

- Capacity building initiatives to sensitize and train the staff of the commercial banks, RRBs and RCBs for effective delivery of financial literacy.
- Training for BC/BFs of banks and reimbursement of examination fees

NABARD has advised banks (scheduled commercial banks, RCBs, RRBs) to draw up state-wise quarterly plans for support from FIF towards financial and digital literacy camps by their branches and FLCs. These plans would have to cover target groups such as SHGs, students; senior citizen; farmers; small entrepreneurs etc. giving special attention to excluded blocks, areas based on FIPs of Banks and discussions in SLBC Sub Committee on FI and State Government priorities. NABARD RO would also be holding quarterly review with banks for projects funded out of FIF and the progress would also be reviewed in FI Sub Committee of SLBCs.

G. SIDBI

- Samriddhi, the virtual assistant was launched by SIDBI on the Udyami Mitra portal on April 02, 2018. The virtual assistant guides budding entrepreneurs across a wide gamut of topics ranging from kinds of loans to handholding support. (operational in English and Hindi)
- A “Bankability Kit for MSE Entrepreneurs” in bilingual format has been hosted on the portal. This is a one stop guide for entrepreneurs to assess themselves, give an overview of what bankers look at, tips to communicate with banks, financial products for MSMEs, besides other important components.
- Certified Credit Counsellors and CCIs have been empaneled and onboarded on Udyami Mitra platform to strengthen the supply side by enhancing access to credit as also giving thrust to demand side issues of MSMEs particularly those at the bottom of pyramid.
- Udyami Mitra Portal aims to aims at instilling ease of access to MSMEs financial and non-financial service needs. The portal also hosts 325 project profiles covering 40 industrial sectors for reference purpose. More than 7618 handholding agencies have attended to 50680 information and other important needs of aspirant entrepreneurs. Certified Credit Counsellors are also assisting entrepreneurs in enhancing their knowledge and connect them appropriately to lenders.
- SIDBI with the support of the nationwide Common Service Centres (CSCs) has delivered an Entrepreneurship Awareness campaign or the Udyam Abhilasha project which focused on 115 aspirational districts across 28 states. These 115 districts account for more than 20% of the country’s population and cover over 8,600 Gram panchayats. During the campaign around 470 training locations were covered with over 2.25 lakh hours of inputs given to 18000+ youths (including about 35% women)

- SIDBI has positioned Hauz Khas Metro Station (in New Delhi) as a thematic station and disseminating information amongst masses. This initiative aims at connecting people with initiatives like Pradhan Mantri Mudra Yojana, CGTMSE, Social Security schemes, SIDBI offerings, GOI initiatives, etc.
- During the recent Kumbh Mela, SIDBI initiated a special project by setting up a Swavalamban stall and created financial awareness aimed at spreading entrepreneurship culture across the nation through games (Kaun Banega Udyami), Nukkad Natak/ puppet shows, financial literacy videos and disseminated information on schemes such as MUDRA, CGTMSE, Standup India and so on.

H. NPCI

- NPCI started working with Public Sector Banks (PSUs) and private sector banks to create awareness and literacy sessions on RuPay, IMPS, AePS, and USSD - *99#. NPCI was involved with cooperative and regional rural banks. While conducting awareness and literacy sessions NPCI also distributed posters, ATM screen, web banners, SMS, emailers, etc. for digital payment literacy and fraud awareness.
- Disseminating digital payment literacy to corporate employees and beneficiaries with the help of these agencies. Currently, apart from the banks NPCI is also associated with Indian Railways, OMCs, NABARD, Education Institutes, Corporate CSR, NULM, MFIs, BCs, NGOs, Agritechs, FinTechs, etc to promote digital payment literacy and awareness.
- Entered Limca Book of Records in the year 2017 for conducting 120 e-Payment Literacy camps simultaneously across the country on September 8, 2015, the world Literacy Day. 23,930 customers attended workshops.

